twitter.com/divyadelhi | facebook.com/divyadelhi | infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

In Just 500 ₹
Get
Video AD +2 Days Free Marketing
Advertise On Leading News Channel
9891255609
9354173558
9891221238

DD दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 149, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

लोकसभा से पारित हुआ तटीय नौवहन विधेयक-2024

नई दिल्ली
लोकसभा ने गुरुवार को तटीय नौवहन विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक देश के तटीय जल के भीतर व्यापार कर रहे जहाजों को विनियमित करता है। विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन संबंधी कानूनों को समेकित और संशोधित करना, तटीय व्यापार और घरेलू भागीदारी को बढ़ावा देना है। विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के पास सुरक्षा और वाणिज्य के लिए नागरिक स्वामित्व वाला तटीय बेड़ा हो।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत और परिवहन मंत्री सवार्नंद सोनेवाल ने कहा कि विधेयक तटीय नौवहन में देश की अपार, अप्रकाशित क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। साथ ही यह रणनीतिक और भविष्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के रूप में कहा जाता है। इस दौरान मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र में प्राप्त उल्लेखनीय सफलताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कार्गो हैंडलिंग में हमारी वृद्धि 103 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 2014 में यह 80 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़कर 1630 करोड़ मीट्रिक टन हो गई है। पोर्ट रैंकिंग में हमारा स्थान 2014 में 54वां था। आज हम 38वें स्थान पर हैं। बीते 10 साल में दुनिया के बेहतरीन 100 पोर्ट में भारत के 9 पोर्ट शामिल हुए हैं।

जगुआर के दुर्घटनाग्रस्त होने की होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी

नई दिल्ली
गुजरात के जामनगर में बुधवार रात फाइटर जेट जगुआर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। भारतीय वायु सेना ने गुरुवार को इस दुर्घटना के लिए तकनीकी खराबी को शुरूआती कारण बताया है। वायु सेना ने आधिकारिक जानकारी में बताया है कि जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भर रहा दो सीटर जगुआर विमान बुधवार को रात में 10.20 बजे रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को आबादी क्षेत्र से बाहर निकालने की पहल की, ताकि एयरफील्ड और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे।

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 को पारित किया

वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया

नई दिल्ली
राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को आज आधी रात के बाद पारित कर दिया। इस पर सदन में करीब 12 घंटे से अधिक बहस हुई। जहां सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद बताया, वहीं विपक्ष के सदस्यों ने इसे " मुसलमान-विरोधी" कहकर इसकी आलोचना की। विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को अस्वीकृत किए जाने के बाद विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। वक्फ (संशोधन) विधेयक की प्रमुख धाराओं में वक्फ ट्रिब्यूनलों को मजबूत करना, एक संरचित चयन प्रक्रिया को लागू करना और विवाद निपटान की दक्षता को बढ़ाने के लिए एक निश्चित कार्यकाल स्थापित करना शामिल है। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। किरेन रिजिजू ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जब यह बिल शुरूआत में जो ड्राफ्ट हुआ था और आज जो बिल हम पास कर रहे हैं, दोनों की तुलना करने पर आप पाएंगे इसमें चर्चा कर-के कितने सुधार किए गए हैं। इस सदन के कई सदस्य भी जेपीसी में सदस्य रहे हैं। उन्हीं सदस्यों के सुझाव पर कलेक्टर के मामले में तथा कई अन्य सुधार किए गए हैं। सदन के कई सदस्य जो स्वयं जेपीसी में बैठते हैं और आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनकी बात नहीं सुनी गई। जितना आप चाहते हैं, उतना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जेपीसी में बहुमत को मंजूरी मिल गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? आज आप लोग एक बात बार-बार दोहरा रहे हैं कि आप मुसलमानों की चिंता क्यों करते हैं और कहते हैं कि भाजपा और हमारे एनडीए के लोगों को भाजपा या मुसलमानों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

वक्फ संशोधन विधेयक-2025 में सुधार कम, संशय ज्यादा है: अभिषेक मनु सिंघवी

नई दिल्ली
राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस बिल में सुधार कम और संशय ज्यादा है। न्याय कम और पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया, यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसको संशोधन कम, साज़िश ज्यादा कहा जाना चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। उन्होंने कहा कि बिल के क्लॉज 11 के तहत शत-प्रतिशत सदस्य प्रादेशिक वक़्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे।

असंवैधानिक है वक्फ संशोधन विधेयक: प्रो. रामगोपाल

नई दिल्ली
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि कल मध्यरात्रि तक लोकसभा में चर्चा चली चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ। दोनों तरफ से अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए लेकिन संसद में पैदा हुई असमंजस की स्थिति से देश की जनता में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग संसदीय लोकतंत्र का नुकसान कर सकते हैं। सारे धर्मों के लोगों के साथ सामान व्यवहार होना चाहिए। दुनिया में मुस्लिम लोगों की आबादी से कहीं ज्यादा देश में इनकी आबादी है। ऐसे में उनको नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार पर हमला बोलते हुए रामगोपला ने कहा कि जो सरकार अतीत में जो किया है जनता उससे संतुष्ट नहीं है। जो बातें सरकार ने कहीं उन वायदों को न ही पूरा किया और न ही अमल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सांसदों ने अपने भाषण में बार बार जमीन औ? पैसे की लेकिन इस विधेयक पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। अलग-अलग रास्ते पर चलने वाले लोगों को मिलकर चलना होगा तभी देश की तरक्की होगी। प्रोफेसर मनोज झा की बात की ओर इशारा करते हुए रामगोपाल ने कहा कि आज देश लोकतांत्रिक देश से सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए इस स्थिति को पैदा नहीं होना देना चाहिए।

वक्फ की तुलना ट्रस्ट से नहीं हो सकती: कपिल सिब्बल

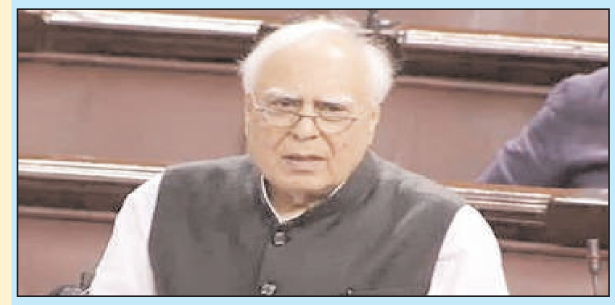

नई दिल्ली
राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ की तुलना ट्रस्ट से नहीं की जा सकती है। ट्रस्ट में संपत्ति को बेचा जा सकता है, लेकिन वक्फ में ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह वह संपत्ति है जिसे आप अल्लाह को देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिब्बल ने चर्चा में भाग लेते हुए वक्फ विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 2013 के कानून में किसी को भी वक्फ को संपत्ति देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे बदल दिया है। अब केवल पांच साल से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर पायेगा। सिब्बल ने कहा कि वक्फ एक कानूनी संस्था है। इसमें पहले से ही सरकार की ओर से सदस्यों को नामित किया जाता था। सरकार इसपर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि समस्या की वजह मुतवल्ली से जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक के प्रावधानों से अब वक्फ की कब्जा की गई संपत्ती पर कब्जा कायम रहेगा।
राज्यसभा में चर्चा के दौरान केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुद्दा उठाया कि सदन के वरिष्ठ सदस्य अपनी बात रखने के बाद चले जाते हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर उनके रखे गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से बैंकॉक में मुलाकात की। गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने स्वागत किया। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी।

भारत सुरक्षित हाथों में है, जनादेश सरकार के साथ: जितिन प्रसाद

नई दिल्ली
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से "सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण" के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की। जितिन प्रसाद ने कहा कि देश एक मजबूत और स्थिर सरकार के सुरक्षित हाथों में है। जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि जनादेश सरकार के साथ है। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, नवप्रवर्तकों का स्टार्टअप समुदाय तथा आपके द्वारा प्रस्तुत नए विचार, भारत को सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन लाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, आपको दुनिया को बताना होगा कि भारत चुनौतियों के लिए तैयार है। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास कौशल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास चुस्त सरकार है, भारत सुरक्षित हाथों में है। जनादेश सरकार के साथ है। नीतियां मजबूत और स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप बहुत बढ़िया मूल्य निमार्ता हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि न केवल हितधारक और सरकार बल्कि आम आदमी भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र या विकसित भारत बनने का अपना सपना पूरा करे। प्रसाद ने कहा कि अब चर्चाओं को वातानुकूलित कमरे की बैठकों से आगे बढ़ाकर जमीनी स्तर पर ऐसे मामलों पर ले जाना चाहिए, जो वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित करें। उल्लेखनीय है कि तीन से पांच अप्रैल तक चलने वाले स्टार्टअप महाकुंभ में 50 से अधिक देशों की स्टार्टअप कंपनियां, निवेशक और उद्योग जगत के दिग्गज भाग ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर

पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, वेतन लौटाने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के करीब 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नियुक्तियां फर्जी तरीके से की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया, उन्हें वेतन वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है जो दागी नहीं हैं। कोर्ट ने 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने सात मई 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह भर्ती प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है। कोर्ट ने कहा था कि 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना अफसरों का काम है। पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में पढ़ाई ठप हो जाएगी। याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर बिना किसी भी हलफनामे और मौखिक दलील के आधार पर ही मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दीं।

ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद एक्शन मोड में सरकार

नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप की स्थिति बना दी है। टैरिफ का ऐलान होने के बाद से ही भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण अलग-अलग सेक्टर्स पर पड़ने वाले निगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप की घोषणा के साथ भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इससे भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले असर की समीक्षा में जुट गए हैं। केंद्र सरकार ने टैरिफ की समीक्षा के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम में अलग-अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है, जो टैरिफ के असर का अध्ययन करने के बाद उससे निपटने के उपायों पर प्रस्ताव पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि शुरूआती समीक्षा में इस बात की भी संभावना व्यक्त की गई है कि अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के कारण कुछ सेक्टर्स को नुकसान जरूर होगा, लेकिन कुछ सेक्टर ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से फायदे में रह सकते हैं। टैरिफ का भारत पर पड़ने वाले असर का समग्र अध्ययन करने के लिए अलग-अलग देश पर लगाए गए टैरिफ की समीक्षा की जा रही है।

लोकसभा में पांच घंटे चला शून्यकाल, 202 सदस्यों ने उठाए अपने क्षेत्र के विषय

नई दिल्ली
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल का समय बढ़ाया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को संसद में अपने क्षेत्र की बात रखने का बड़ा अवसर मिला। आज लोकसभा में 5 घंटे से अधिक समय तक शून्य काल चला और इसमें 202 सांसदों ने अपनी बात रखी। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्य काल होता है और इसमें बिना किसी अग्रिम सूचना के मुद्दों को उठाया जा सकता है। इससे पहले 18 जुलाई 2019 को विस्तारित शून्य काल में 161 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। जानकारी के अनुसार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल को बढ़ाकर सदस्यों को अपनी बात रखने का वाद किया था। उल्लेखनीय है कि कल लोकसभा में देर रात तक वक्फ संशोधन विधेयक पर बैठक चली थी।

श्रृंगवेरपुर का विकास भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का प्रतीक- सीएम योगी

प्रयागराज
सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगा दी है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागीरी नहीं चलेगी, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने यहां प्रभु श्री राम एवं राजा निषाद से जुड़ी कथाओं तथा 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपये की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।

श्रृंगवेरपुर का विकास भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का प्रतीक- सीएम योगी

सीएम योगी ने श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि निषाद राज पार्क भगवान राम व निषाद राज की मित्रता का भव्य स्मारक है। सीएम योगी ने पार्क का निरीक्षण किया और कहा कि हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर भगवान राम ने कदम रखा था। निषाद राज ने मित्रता का धर्म निभाते हुए भगवान राम को गंगा पार कराई और चित्रकूट तक उनका साथ दिया। आज वही मित्रता बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच दिख रही है। यह इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि जहां भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, वहां घाटों का निर्माण और सुंदरीकरण होगा।

मप्र में अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे सीएम राइज स्कूल: डा. मोहन यादव

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को स्कूल चलें हमें अभियान के शुभारंभ अवसर पर इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल का नाम ऐसा लगता था, जैसे अंग्रेजों के जमाने का हो, इसलिए इसे बदलकर सांदीपनि ऋषि के नाम पर किया गया है।दरअसल, मध्य प्रदेश में आज (एक अप्रैल) से नया शैक्षणित सत्र शुरू हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर भोपाल के शासकीय नवीन उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी (ओल्ड कैंपियन) में स्कूल चलें हम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की शिक्षा भी किसी से कमतर नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी कई महान व्यक्तित्वों ने विश्वभर में भारत का नाम रोशन किया है। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और कड़ी मेहनत के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। उन्होंने इस अवसर पर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया। इसके अलावा

राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे संवाद किया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इस साल एक अप्रैल से जब छात्र अपने विद्यालय में प्रवेश करेंगे, तो शासन द्वारा दी जाने वाली किताबें उनके बैग में पहले से उपलब्ध होंगी। यह पहली बार हुआ है कि पूरे राज्य के प्रत्येक जिले में शैक्षणिक सामग्री समय पर वितरित कर दी गई है। नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे। जुलाई में बेटियों को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी मौजूद रहे। इस राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 92 हजार सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 85 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं।

देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर छह हुई : शाह

एजेंसी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान के तहत देश के छह जिलों को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के दुष्प्रभाव से मुक्त कराया है। इससे वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र छह रह गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, आज हमारे देश ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या को 12 से घटाकर मात्र 6 कर एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मोदी सरकार

नक्सलवाद के प्रति निर्मम दृष्टिकोण और सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या 38 थी। इनमें सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है, चिंताजनक जिलों की संख्या भी 9 से घटकर 6 हो गई है और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी 17 से घटकर 6 हो गई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा), झारखंड का 1 (पश्चिमी सिंहभूम) और महाराष्ट्र का 1 (गढ़चिरौली) शामिल है। इस प्रकार कुल 38 प्रभावित जिलों में से चिंताजनक के जिलों की संख्या नौ से घटकर छह रह गई है।

बाघों को शांत रहने की जगह देना हमारी जिम्मेदारी: खरगे

एजेंसी

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि भले ही हमारे यहां टाइगर प्रोजेक्ट के जरिए बाघों का संरक्षण करने से उनकी आबादी बहुत अच्छी है फिर भी अवैध तरीके से उनका शिकार करने का प्रयास चिंताजनक है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। श्री खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाघों के संरक्षण के लिए किए कार्यों को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की दूर दृष्टि के कारण देश में आज बाघों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है और उन्हें सुरक्षित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा ÷52 साल पहले, भारत ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस भव्य जानवर की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों, उनके आवासों और हमारे जंगलों की

संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा की। श्री खरगे ने कहा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, बाघ को अलग-थलग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता। यह एक विशाल और जटिल जैव-क्षेत्र के शीर्ष पर है। मानव घुसपैठ, वाणिज्यिक वानिकी और मवेशियों के चरने से खतरे में पड़े इसके आवास को सबसे पहले अछूता बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा आज, भले ही दुनिया की 70 प्रतिशत बाघ आबादी भारत में है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में नए तंत्रों के माध्यम से अवैध शिकार की परेशान करने वाली रिपोर्टें आई हैं। हमारे बाघों को अंधाधुंध शिकार से बचाने और शांतिपूर्ण मानव-पशु सह-अस्तित्व के लिए परिस्थितियां स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठाने में हमारी जिम्मेदारी है।

धामी ने की चार मैदानी जनपदों के विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जन भावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, हरिद्वार जनपद में ग्राम औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंदरीशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर किया जाना है।

समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है और आगे भी रहेगी : अखिलेश यादव

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इससे पहले वक्फ बिल को लेकर सियासी पारा गरमा चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भाजपा कर रही है, वह पूरा कंट्रोल अपने पास चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा का इतिहास जिस तरह के फैसलों से भरा है, उससे जो परिणाम भाजपा चाहती थी, वह नहीं आए। भाजपा का हर फैसला वोट के

लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है और आगे भी रहेगी। वे (भाजपा) पूरा नियंत्रण अपने पास चाहते हैं। इस देश ने वह समय भी देखा है, जब प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई। जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले, वह (भाजपा) लोगों से कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, वक्फ के माध्यम से वह यह संदेश देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी नहीं दी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इनका वोटर भी इनसे नाराज है। वह कहते थे कि हम (विपक्ष) तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे (भाजपा) ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं? ईद पर जो किट दी है, क्या वह तुष्टीकरण में नहीं आएगा? इनको पता है, इनका वोट बैंक खिसक गया है। अभी तक ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे। अब इनकी कोशिश मुसलमानों को भी गुमराह करने की है।

मणिपुर में 24 घंटे में पांच उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान अलग-अलग अभियानों में इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों के विभिन्न इलाकों से केसीपी-नोयोन समूह के पांच सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि वे कथित रूप से जबरन वसूली और धमकी देने में संलिप्त थे। उनके पास से एक 9 एमएम पिस्तौल, तीन जिंदा राउंड के साथ कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया।

राजस्थान में फैक्टरी से गैस लीक, तीन की मौत

एजेंसी

अजमेर। राजस्थान के ब्यावर के बाड़िया क्षेत्र में तेजाब फैक्टरी के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित तीन लोगों की मौत हो गई। तीन लोगों की हालत अब भी गंभीर है। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों को ब्यावर और अजमेर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गैस के असर से कई पालतू जानवरों और लावारिस कुत्तों की भी मौत हुई है।

यह वाकया ब्यावर थाने के बाड़िया क्षेत्र की सुनील ट्रेडिंग कंपनी में सोमवार रात हुआ । हादसे में कंपनी मालिक सुनील सिंघल की मौत हो गई, जो रातभर गैस को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अजमेर रेफर किया गया। सोमवार रात को ही उनकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह एक और पीड़ित नरेंद्र सोलंकी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जेएलएन हॉस्पिटल में दो लोग अब भी आईसीयू में है और एक गैसकांड प्रभावित का जनरल वार्ड में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े टैंकर से

नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही गैस आसपास के रिहायशी इलाके में फैल गई। घरों के अंदर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। लोगों को दम घुटने के साथ आंखों में जलन की भी परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रात में ही गैस लीकेज पर काबू पा लिया गया। एहतियातन फैक्टरी के आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया गया। स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत ने फैक्टकी को सीज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोहाली कोर्ट ने रेप मामले में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा

मोहाली । मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया था। इस पादरी पर एक महिला के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया है।

युवा भारत के भविष्य का निर्माता :गुप्ता

एजेंसी

नयी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने युवाओं को भारत के भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि विकसित भारत युवा संसद नयी पीढ़ी नीतियों और समाधान आधारित सोच के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आज राज्य स्तरीय 'विकसित भारत युवा संसद' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधानसभा के सदस्य डॉ. अनिल गोयल,रविंद्र सिंह नेगी और रविकांत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, दिल्ली के राज्य निदेशक लाल सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक सर्वण कटारिया, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी

संजय बेनीवाल, आईआईटीएम की निदेशक डॉ. रचना राणा, और गीतकार अनिरुद्ध पांडे भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। युवा संसद में दिल्ली के विभिन्न जिलों से चयनित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए थे। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सार्थक अरोरा (प्रथम स्थान), लावण्या कार्की (द्वितीय स्थान), दिव्यांशी पांडा(तृतीय स्थान) प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो भारतीय संसद में आयोजित होगी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई, जहां महाराजा अग्रसेन स्कूल के छात्रों ने गणेश स्तुति प्रस्तुत की। इस युवा संसद का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व कौशल, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ को विकसित करना है। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा, नेहरू युवा केंद्र संगठन और दिल्ली विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह युवा संसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है, जिसमें भारत की राजनीति में 01 लाख युवा नेताओं को लाने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा, भारत के युवा केवल विकास के लाभार्थी नहीं, बल्कि इसके भविष्य के निर्माता भी हैं। विकसित भारतञ्च2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप यह युवा संसद नई पीढ़ी को नीतियों और समाधान-आधारित सोच के प्रति जागरूक बनाने का कार्य कर रही है। श्री लाल सिंह ने इस सफल आयोजन के लिए दिल्ली विधानसभा और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट से एक ही परिवार के आठ की मौत

एजेंसी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के पाथरप्रतिमा इलाके में सोमवार रात एक पटाखा कारखाने में हुए भीषण विस्फोट हो गया। जिसके कारण एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में चार बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें दो की उम्र एक साल से भी कम थी। घटना के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उस घर में लंबे समय से अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे। सोमवार रात पाथरप्रतिमा के ढोलाहाट थाना क्षेत्र के दक्षिण रायपुर इलाके में जोरदार धमाकों के साथ आग लग गई। विस्फोट के कारण

घर भीषण आग लग की चपेट में आ गया, जिससे परिवार के आठ सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 65 वर्षीय अरविंद बनिक, 80 वर्षीय प्रभावती बनिक, 28 वर्षीय सांत?वना बनिक, नौ साल का अर्णब बनिक, आठ महीने की अस्मिता बनिक, छह साल की अनुष्का बनिक और छह महीने का अंकित बनिक शामिल हैं। वहीं, तुषार बनिक की पत्नी रूपा बनिक गंभीर रूप से झुलस गई थीं, लेकिन बाद में उनकी भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस घर में लंबे समय से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि परिवार के पास ग्रीन क्रैकर (पर्यावरण अनुकूल पटाखे) बनाने का लाइसेंस था। फिर भी इलाके के लोगों को संदेह है कि इस लाइसेंस की आड़ में अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर पहले ही इस अवैध पटाखा निर्माण को रोका जाता तो यह हादसा टल सकता था। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए कई बार जिला पुलिस अधिकारियों को संपर्क किया गया लेकिन सभी ने मुंह बंद कर रखा है।

भारत दौरे पर चिली के राष्ट्रपति बोरिक, विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से मुलाकात कर खुशी हुई। हमारे दीर्घकालिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनकी बातचीत से नई साझेदारियां और अधिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले दिन में

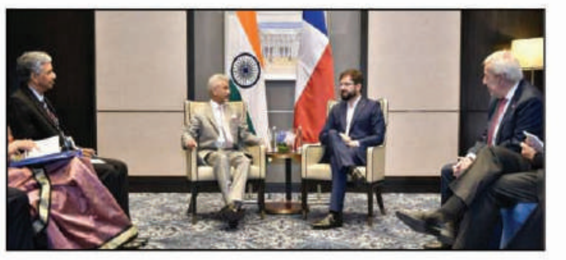

बोरिक पांच दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) पाबित्रा मार्गेरिटा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हवाई अड्डे पर उतरने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने पोस्ट किया, आपका स्वागत है, राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक! चिली के राष्ट्रपति बोरिक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति बोरिक के साथ मंत्रियों, संसद सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और भारत-चिली सांस्कृतिक आदान-प्रदान में शामिल प्रमुख चिलीवासियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। चिली के राष्ट्रपति 5 अप्रैल को अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा भी करेंगे। भारत पहुंचने के बाद चिली के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह 6:30 बजे दिल्ली में। ऐसे समय में जब बहुपक्षीय सहयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी है।

असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के मो. युनूस के बयान को बताया आपत्तिजनक

एजेंसी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के उस बयान की कड़ी निंदा की है। जिसमें यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों को 'लैंडलॉक्ड' बताने और बांग्लादेश को उनका समुद्री मार्ग का संरक्षक बताने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने इसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर मोहम्मद यनुस के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि यह बयान भारत के रणनीतिक 'चिकन नेक' कॉरिडोर की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से, देश के भीतर भी कुछ तत्व इस गलियारे को तोड़कर पूर्वोत्तर को मुख्यभूमि से अलग करने की बातें कर चुके हैं, जो गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। उन्होंने इस क्षेत्र में मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर और आसपास बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है। साथ ही, ऐसे वैकल्पिक मार्ग भी खोजे जाने चाहिए, जो इस गलियारे पर निर्भरता कम कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही रणनीति और नवाचार के जरिए इसे संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मोहम्मद यूनुस के इस भड़काऊ बयान को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि यह गहरे रणनीतिक मंसूबों और लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्री श्री श्री स्वामीगलु को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

एजेंसी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने उनके असाधारण प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें करुणा और अथक सेवा के प्रतीक के रूप में सराहा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, परम पूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु की जयंती के विशेष अवसर पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। उन्हें करुणा और अथक सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे निस्वार्थ कार्य समाज को बदल सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने बनासकांठा की फैक्टरी में हुए हादसे पर दुख जताया, मुआवजा देने की घोषणा की

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में एक फैक्टरी में हुए धमाके में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बनासकांठा (गुजरात) की एक पटाखा फैक्टरी में हुआ हादसा बेहद पीड़ादायक है। अबतक 18 मजदूरों की जान गई है और कई घायल हुए हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

साहित्यकार डॉ. कमल किशोर गोयनका का निधन

नई दिल्ली। हिन्दी के प्रख्यात लेखक और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के साहित्य के सर्वोत्तम विद्वान शोधकर्ता डॉ. कमल किशोर गोयनका का निधन हो गया। उनके बेटे संजय ने बताया कि उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में सुबह लगभग 7:30 अंतिम सांस ली। उनके छोटे पुत्र राहुल विदेश में हैं। इसलिए उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11 अक्टूबर 1938 को जन्मे कमल किशोर गोयनका को वर्ष 2014 के लिए 24वें व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक 'प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन' के लिए दिया गया था। उन्हें व्यास सम्मान के साथ-साथ उदय राज स्मृति सम्मान भी प्राप्त था। उन्हें प्रेमचंद साहित्य का अप्रतिम मर्मज्ञ माना जाता है। उनका योगदान केवल प्रेमचंद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हिंदी साहित्य के गम्भीर शोध, आलोचना और प्रवासी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी असाधारण कार्य किया। डॉ. गोयनका चार दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के शिक्षक रहे और रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए।

बजिंदर सिंह को उम्रकैद, स्वाति मालीवाल ने फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली। मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बजिंदर सिंह को यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा का स्वागत करती हूं। बजिंदर सिंह झूठा और पाखंडी आदमी है। इसने अपने पाखंड के चलते पिछले कई सालों में कई कनवर्जन भी किए हैं। कभी ये किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का नाटक करता है, कभी ये किसी विकलांग को ठीक कर देने का पाखंड रचता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि बजिंदर सिंह को पिछले कई सालों से पंजाब सरकार संरक्षण क्यों दे रही है। बजिंदर सिंह को सरकार ने हाई सिक्योरिटी भी दे रखी है। आशा करती हूं कि इस मामले में जांच अब और तेज होगी। वहीं, बजिंदर के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि कोर्ट की तरफ से उम्रकैद की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। हमारी तरफ से मांग की गई थी कि कम से कम सजा दी जाए। हमने कहा था कि बजिंदर के 3 छोटे बच्चे हैं, पत्नी बीमार हैं। इस मामले में जल्द ही हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट विधानसभा में की पेश

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में प्रदूषण और उसके रोकथाम से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक का डेटा अविश्वसनीय रहा। उचित निगरानी के लिए आवश्यक प्रदूषक सांद्रता डेटा उपलब्ध नहीं था और लेड के स्तर की माप भी नहीं की गई। प्रदूषण स्रोतों पर वास्तविक समय का डेटा न होने से जरूरी अध्ययन नहीं हो सके। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का कोई आकलन नहीं किया गया, जिससे स्रोत-विशिष्ट रणनीतियां बनाने में मुश्किलें आईं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 में बेंजीन का स्तर तय सीमा से अधिक था, लेकिन पेट्रोल पंपों से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावी निगरानी नहीं हुई। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी चिंता का विषय रही। दिल्ली में 9,000 बसों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 6,750 बसें उपलब्ध थीं।

भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता करने पर हुए सहमत

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और दक्षिणी अमेरिकी देश चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता(सीईपीए) करने पर सहमत हुए हैं। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने सीईपीए वार्ता के प्रारंभ होने का स्वागत किया। इससे व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन और जन संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चिली में 4

नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किये जाने को प्रेरणादायक बताया। दोनों देश अंटार्कटिका में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। वहीं चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार का समर्थन करता है। दोनों देश अंटार्कटिका में अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। 'शूट इन चिली' कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने देश को फिल्म निर्माण के लिए पेश करते हैं। चिली के राष्ट्रपति बोरिक 1-5 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वे आगे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री ने अतिथि के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण एवं व्यापारिक साझेदार है। चिली क्षेत्र का एकमात्र देश था जिसने 1947 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष दूत भेजा था।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 संसद से पारित

एजेंसी

नई दिल्ली ।राज्य सभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (आईआरएमए) को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना है। विश्वविद्यालय का नाम सहकारी आंदोलन के नेता और अमूल डेयरी के संस्थापक त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा, जो भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे और अमूल की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।। गुजरात के आणंद में स्थापित होने वाला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी शिक्षा पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शोध और विकास, वैश्विक उत्कृष्टता और सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। यह सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के विजन का हिस्सा है। त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल के नाम पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय में हर साल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है और 8 लाख सहकारी संस्थान हैं, जिनसे 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई इकाई ऐसी है ।

दो भारतीय युद्धपोत 30 टन राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचे, एक और जहाज रवाना

एजेंसी

नई दिल्ली। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत की ओर से शुरू किये गए ऑपरेशन 'ब्रह्मा' के तहत नौसेना के दो जहाज राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। म्यांमार में भारत के राजदूत भारत ठाकुर ने खाद्य, चिकित्सा आपूर्ति और टेंट सहित 30 टन सहायता सामग्री यांगून के मुख्यमंत्री यू सोई थीन को सौंपी। नौसेना का एक जहाज आईएनएस घड़ियाल आज सुबह विशाखापत्तनम बंदरगाह से यांगून के लिए रवाना हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज करमुक और एलसीयू-52 अंडमान और निकोबार कमान के श्रीविजयपुरम से 30 मार्च को यांगून के लिए रवाना किये गए थे। आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयां, टेंट और आपातकालीन राहत सामग्री लेकर दोनों जहाज आज सुबह यांगून पहुंचे। जहाज के चालक दल ने 30 टन

सामग्री राजदूत अभय ठाकुर के जरिए वहां के मुख्यमंत्री यू सोई थीन को सौंपी। नौसेना का एक और जहाज आईएनएस घड़ियाल आज सुबह विशाखापत्तनम बंदरगाह से यांगून के लिए रवाना हुआ, जिसमें चावल, खाद्य तेल और दवाओं सहित लगभग 440 टन वजनी राहत सामग्री लादी गई है। नौसेना के मुताबिक आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री लगभग 40 टन राहत सामग्री लेकर 31 मार्च को यांगून पहुंचे हैं। दोनों जहाज 29 मार्च को यांगून के लिए 40 टन मानवीय सहायता लेकर रवाना किये गए थे। दोनों जहाजों ने म्यांमार पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया देने वाले क्षेत्र के रूप में भारतीय नौसेना म्यांमार में प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। ऑपरेशन 'ब्रह्मा' के तहत भारतीय वायु सेना के छह विमानों और भारतीय नौसेना के पांच जहाजों से भारत ने बड़े पैमाने पर प्रथम प्रतिक्रिया सहायता यांगून, नेपीता और मांडले तक पहुंचाई है।

स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। स्वच्छता अभियान को मिशन के रूप में आगे ले जाने के मकसद को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सुविधाओं और केन्द्रों पर मंगलवार से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को सर्वोच्च महत्व और प्राथमिकता दी है।

उनके दृष्टिकोण स्वच्छता का मिशन एक दिन का अनुष्ठान नहीं बल्कि आजीवन अनुष्ठान है। इससे प्रेरित होकर 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, स्वच्छता नेताओं और सरकारों के प्रयासों से नहीं बल्कि समाज के

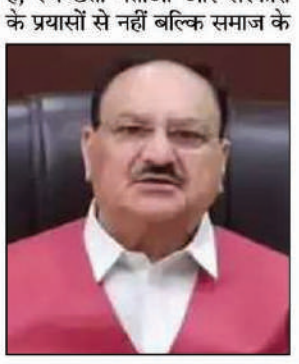

प्रयासों से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आज स्वच्छता अभियान एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। उन्होंने जन भागीदारी की इस भावना को अपनाते हुए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से इससे जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग इस मिशन में उत्साहपूर्वक चैंपियन बनने को अपना व्यक्तिगत मिशन बनाएं। अपने आस-पास और समुदायों के लोगों को इस राष्ट्रीय अभियान में स्वच्छाग्रही बनने के लिए प्रोत्साहित करें, शामिल करें और सशक्त बनाएं। जेपी नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि एक जन आंदोलन न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के कायाकल्प की ओर ले जा सकता है, बल्कि हमारे आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छता के उच्च स्तर से हमारे सामूहिक स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर लाभ हो सकता है।

राज्यसभा ने 'वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक-2025' पारित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसका उद्देश्य देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना और एयरलाइनों एवं पट्टा देने वाले दोनों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है। यह पिछली अनिश्चितताओं के बीच पट्टा उद्योग के लिए स्पष्टता और लाभ प्रदान करता है। यह भारत को वैश्विक विमानन मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक-2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि इस विधेयक पर भारत पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। विधेयक पर चर्चा के जवाब में राममोहन नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून एयरलाइनों और लीज पर देने वाले दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है, जो इस क्षेत्र में लंबे

समय से चली आ रही अस्पष्टताओं को दूर करता है। इस विधेयक से लीज उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए तत्काल कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है। यह विधेयक मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमानों के लिए विशिष्ट केपटाउन प्रोटोकॉल सहित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करता है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऋणदाता किसी भी प्रकार का उपाय अपनाने से पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सूचित करे तथा चूक की स्थिति में एक व्यवस्थागत उपाय प्रस्तुत करे।नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत में घरेलू यात्री बाजार 6.07 लाख था, जो पिछले 10 सालों में बढ़कर 2024 तक 10.63 करोड़ हो गया। इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 4.3 करोड़ से बढ़कर 6.68 करोड़ हो गई। विमानों की संख्या भी 359 से बढ़कर 840 हो गई है। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, जो इस समय बढ़कर 159 हो गए हैं। नायडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नागरिक उड्डयन में हमने जिस तरह की प्रगति देखी है, वह कोई आसान काम नहीं था। यह एक दिन में हासिल नहीं हुआ, बल्कि लगातार प्रयासों से हासिल हुआ। यही कारण है कि आज हम इतनी उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार एयरलाइनों के दिवालिया हो जाने पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाता है। विमान खड़े कर दिए जाते हैं। इससे विमानन उद्योग को तो नुकसान होता ही है लेकिन जो पक्ष विमान पट्टे पर देता है, उसे खासतौर पर बड़ा नुकसान होता है। इसी मामले में स्पष्ट कानून की आवश्यकता को देखते हुए यह विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लागू करने से लीजिंग लागत 8 से 10 प्रतिशत तक कम हो रही है। यह लागत अंततः यात्रियों तक पहुंचेगी और हवाई किराए पर भी इसका असर पड़ेगा। इससे दोनों पक्षों को सहूलियत मिलेगी। यही कारण है कि यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

वेव्स 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' की पंजीकरण संख्या 85,000 के पार

एजेंसी

नई दिल्ली। मुंबई में 1 से 4 मई, तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 85 हजार के पार हो गई है। इसमें 1,100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के विजेताओं को मुंबई में एक भव्य समारोह में 'वेव्स क्रिएटर अवार्ड्स' से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वेव्स से भारत में नवाचार और जुड़ाव की एक लहर पैदा हुई है, जो वैश्विक स्तर पर रचनात्मक प्रतिभा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रहा है। हाई-एनर्जी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन, सॉल्यूशन-ओरिएंटेड ट्रुथ टेल हैकथॉन, दूरदर्शी यंग फिल्ममेकर चैलेंज और कल्पनाशील कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप सहित 32 विविध और सशक्त चैलेंज की विशेषताओं के साथ, सीआईसी क्रिएटर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अन्य प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि

ए.आई अवतार क्रिएटर चैलेंज, डब्ल्यूएएम! एनीमे चैलेंज, ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ट्रेलर मेकिंग कॉम्पिटिशन, थीम म्यूजिक कॉम्पिटिशन और अत्याधुनिक एक्सआर क्रिएटर हैकथॉन सीआईसी को कहानी कारों, डिजाइनरों और डिजिटल इनोवेटर की अगली पीढ़ी के लिए एक निश्चित लॉन्चपैड के रूप में स्थापित करते हैं।

राज्यसभा में उठी न्यायिक सुधारों की मांग, जजों के लिए हो दो साल का 'कूलिंग ऑफ पीरियड'

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज न्यायिक सुधारों का मुद्दा उठाया गया। आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने शून्यकाल के दौरान कहा कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिससे देशवासी चिंतित हैं। अब वक्त आ गया है, जब न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म किये जाने की जरूरत है। राघव चड्ढा ने कहा कि अदालत को हम न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब न्याय की इस चौखट पर जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसे ही माना जाता है कि अदालत की चौखट पर भी देर भले लग जाए लेकिन अन्याय नहीं होगा। समय-समय पर न्यायपालिका ने अपने इस भरोसे को मजबूत भी किया है, लेकिन हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिसके चलते देश चिंतित है। देश में जैसे शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और चुनाव सुधार हुए, उसी तरह से न्यायिक सुधार की जरूरत महसूस हो रही है। ये सुधार ऐसे होने चाहिए जो न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करें। चड्ढा ने कहा कि जजों की नियुक्ति से लेकर उनके रिटायरमेंट तक में सुधार की जरूरत है। जजों की नियुक्तियों में समय-समय पर कॉलेजियम प्रणाली की खामियां, लॉ

कमीशन की रिपोर्ट सामने आई और एनजेएसी जैसे कानून को लाना पड़ा। अब समय आ गया है, जब कॉलेजियम स्वयं ही सुधार करे और नए तरीके खोजे, ताकि पारदर्शिता की कमी और सार्वजनिक जांच की कमी, जिन दो विषयों पर कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है, उसे दूर किया जाए और एक स्वतंत्र पारदर्शी व्यवस्था बने। आज एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए प्वाइंट बेस्ड पूरी पारदर्शी व्यवस्था है। इसी प्रकार से जजों की नियुक्ति के लिए भी पारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम लाया जाया तो देश की जनता में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाओं की पेशकश में सुधार किए जाने की जरूरत है। यह न्यायिक स्वतंत्रता और व्यवस्था में जनता के विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। देश में अनुच्छेद 148 के अनुसार जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर कोई सरकार नियुक्त नहीं कर सकती है। उसी तर्ज पर न्यायाधीशों के लिए भी रिटायरमेंट के बाद कम से कम दो साल का कूलिंग ऑफ मेंडिटरी पीरियड होना चाहिए। इस दौरान सेवानिवृत्त जजों को न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार किसी पद पर नियुक्त करे। यदि ऐसा होगा तो देश की न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास और बढ़ेगा।

भारत-चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शीर्ष नेतृत्व ने संबंधों के महत्व को किया रेखांकित

एजेंसी

नई दिल्ली । भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामना संदेश आदान-प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने चीनी राष्ट्रपति को दिए अपने संदेश में कहा कि स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों और दुनिया के लिए लाभप्रद हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि चीन-भारत संबंधों का विकास दर्शाता है कि 'ड्रैगन और हाथी' के पास आपसी सफलता में भागीदार बनने और लाभप्रद आपसी सहयोग का एहसास करने का सही विकल्प है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष ली किंआग के बीच आदान-प्रदान किए गए शुभकामना संदेश साझा किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत और चीन दो बड़े पड़ोसी देश हैं। यह मानवता के एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध दोनों और दुनिया के लिए लाभप्रद हैं। हमें राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर का उपयोग करते हुए भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास की दिशा में काम के लिए करना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति शी ने कहा कि दोनों पक्षों को चीन-भारत संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना और संभालना चाहिए। दो बड़े पड़ोसी देशों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी विश्वास और आपसी लाभ तथा साझा विकास के लिए साथ मिलकर काम करने के तरीके तलाशने चाहिए। साथ ही संयुक्त रूप से बहुध्रुवीय विश्व और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष ली किंआग ने भी इस अवसर पर शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया।

राज्यसभा में गूंजा जनगणना में देरी का मुद्दा

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा आज संसद में गूंजा। कांग्रेस सदस्य एवं नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे पहले देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना का काम आपात परिस्थितियों और युद्धकाल में भी समय पर किया गया लेकिन इस बार इसमें अधिक देरी हो रही है। खरगे ने कहा कि जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई और विपरीत परिस्थितियों में भी यह काम समय पर हुआ। उन्होंने कहा कि 1931 की जनगणना के दौरान जातिगत जनगणना भी कराई गई थी। उस जनगणना के पहले गांधीजी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण कराना पड़ता है, उसी तरह जनगणना कार्य किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होता है। जनगणना बहुत महत्व का काम होता है। इसमें काफी बड़ी तादाद में लोग लगते हैं। इसमें जनसंख्या के आंकड़ों समेत रोजगार, पारिवारिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और कई प्रमुख पैरामीटर पर डेटा संग्रह करना होता है। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्वयुद्ध और 1971-72 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उस समय जनगणना हुई थी। इतिहास

में पहली बार सरकार ने जनगणना में रिकार्ड देरी की है। सरकार को जनगणना के साथ जातिगत गणना भी करानी चाहिए। क्योंकि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा संग्रह करते ही हैं, अन्य जातियों का भी कर सकते हैं। इसके बावजूद जातिगत गणना और जनगणना दोनों पर सरकार मौन है। जनगणना के लिए इस साल के बजट में भी केवल 575 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। खरगे ने कहा कि दुनिया के 81 प्रतिशत देशों ने इस बीच में कोरोना के बावजूद सफलतापूर्वक जनगणना का काम पूरा कर लिया है, क्योंकि जनगणना में देरी के दूरगामी परिणाम होते हैं। तमाम बुनियादी आंकड़ें नहीं होने के कारण नीतियां प्रभावित होती हैं। उपभोक्ता सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और कल्याणकारी कार्यक्रम जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण करोड़ों नागरिक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। नीति निर्माताओं के पास अहम फैसला लेने के लिए जरूरी और भरोसेमंद डेटा नहीं है। इसके मद्देनजर वे सरकार से यह निवेदन करते हैं कि तत्काल जनगणना और जातिगत गणना का काम शुरू होना चाहिए।

वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और इसे सदन में पास न होने देने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील

एजेंसी

नई दिल्ली । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल 2 अप्रैल को संसद में सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से पहले आज एक बयान में सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और इसे सदन में पास नहीं होने देने की अपील की है। बोर्ड अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि इस गैर-संवैधानिक विधेयक का न केवल वह विरोध करें बल्कि इसे पास न होने दें। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक विधेयक है और इससे वक्फ संपत्तियों और वक्फ बॉर्डों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के जरिए वक्फ एक्ट को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने भाजपा के सहयोगी दलों और अन्य सेकुलर राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील की है कि वह बीजेपी को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दें और वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें और संसद में इस विधेयक को पास नहीं होने दे। उन्होंने कहा कि वैसे भी संसद से पास वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में मस्जिदों में मंदिरों की तलाश का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। अब अगर यह वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर हो गया तो वक्फ संपत्तियों पर सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए उस पर कब्जा करने की हरकतें बढ जाएगीं और कलेक्टर और डीएम के जरिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संसोधनों के जरिए बोर्डों को खत्म करने की साजिश की जा रही है और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लाकर वहां पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

संपादक की कलम से

आसान नहीं है डगर तीसरे टर्म की

बेशक, लोकसभा चुनाव में लगे धक्के से, जिसमें चार सौ पार के नारों से भाजपा, साधारण बहुमत से काफी नीचे, सिर्फ दो सौ चालीस सीटों पर आ टिकी थी, उसके बाद हुए विधानसभाई चुनावों में जीत जुगाड़ने के जरिए, भाजपा कम से कम मानसिक रूप से काफी हद तक उबरने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से हुए प्रमुख विधानसभाई चुनावों में दिल्ली से पहले तक भाजपा, वैसे तो हरियाणा तथा महाराष्ट्र की दो विधानसभाओं में ही जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, जबकि झारखंड तथा जम्मू-कश्मीर में, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बावजूद, इन दो जीतों के सहारे ही भाजपा ने, जिसे अपने मनमुताबिक आख्यान गढ़ने तथा मीडिया पर अपने नियंत्रण के जरिए उसे चलाने में खास महारत हासिल है, सफलता के साथ यह माहौल बना दिया था कि लोकसभा चुनाव तो एक विचलन था और आमतौर पर जनता फिर से भाजपा के पीछे गोलबंद हो चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से, यह छवि और भी मजबूत हुई है कि मोदी के नेतृत्व में संघ-भाजपा जोड़ी ही चुनावी अजेयता फिर से लौट आई है और यहां से आगे मोदी राज की जीत ही जीत है। सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं, आम तौर पर राजनीतिक जीत भी

उनके इसी भरोसे की अभिव्यक्ति, मोदी राज के तेजी से ऐसे कदमों के रास्ते पर बढ़ने में होती है, जो सबसे बढ़कर आरएसएस के बहुसंख्यकों के अपने पक्ष में सुदृढ़ीकरण और बढ़ते हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के एजेंडे की ओर ले जाते हैं। बेशक, यह किन्हीं खास कदमों का या आरएसएस द्वारा उठायी गयी खास मांगों तक ही सीमित सवाल नहीं है। मोदी राज के तीसरे कार्यकाल के करीब ग्यारह महीनों में खासतौर पर भाजपायी राज्य सरकारों के सहारे, हर साधारण से साधारण मुद्दे का सांप्रदायिक गोलबंदी के हथियार में तब्दील किया जाना, इस देश ने देखा है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक और अयोध्या में तब्दील किया जाना भी शामिल है। इसमें महाकुंभ का ही नहीं, होली-ईद आदि सब का खुल्लमखुल्ला सांप्रदायीकरण भी शामिल है और भाजपा-शासित राज्यों में खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुल्लमखुल्ला भेदभाव भी। जाहिर है कि आरएसएस के पुराने एजेंडे के अनुरूप, समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू कर, आगे बढ़ाया जाना भी इसमें शामिल है।

इसी के हिस्से के तौर पर, संघ-भाजपा ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक हथियार गढ़ा और आगे कर दिया। बहरहाल, तभी इस मुद्दे पर वर्तमान मोदी सरकार के समर्थन की सीमाएं सामने आ गईं। जहां लोकसभा में इस विधेयक के पेश किए जाने के बाद, उसे न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं खुद सत्ताधारी एनडीए में शामिल तेलुगू देशम तथा जनता दल-यूनाइटेड जैसी पार्टियों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विरोध का भी सामना करना पड़ा; ये पार्टियां संघ-भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे का ज्यों का त्यों अनुमोदन करने में असुविधा महसूस कर रही थीं। इसी का नतीजा था कि एक दुर्लभ पैंतरा अपनाते हुए, मोदी राज को इस विधेयक का संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाना स्वीकार करना पड़ा, ताकि इस पर विभिन्न पक्षों की और विस्तार से राय ली जा सके। यह एक प्रकार से इस विधेयक के ठंडे बस्ते में डाले जाने का ही पैंतरा था और उसे आम तौर पर उसी रूप में देखा जा रहा था।

लेकिन, संभवतः इसी बीच हासिल हुई प्रभावी जीतों से बढ़े हुए आत्मविश्वास के चलते, संघ-भाजपा राज ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उसके पक्के एजेंडे को आगे बढ़ाने के जरिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए, इस विधेयक को ठंडे बस्ते से बाहर निकाल लिया है। अब इस विधेयक को दोबारा लोकसभा में आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन, इसी बीच सामने आए घटनाक्रम ने, इस विधेयक के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के पुनर्जीवित किए जाने की सुगबुगाहट होने के बाद से, धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पा?टयों ने और भी दृढ़ता तथा स्पष्टता के साथ इसके खिलाफ आवाज तो उठायी ही है, इसके खिलाफ खुद मुस्लिम समुदाय भी एक स्वर से विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। यहां तक कि इस बार रमजान-ईद के मौके पर, करोड़ों मुसलमानों ने काली पट्टियां बांधकर, इसके खिलाफ शांतिपूर्ण किंतु विराट सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं।

इस सब का नतीजा यह हुआ कि एनडीए में भाजपा के, खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने वाले सहयोगियों को संघ-भाजपा को परोक्ष रूप से यह संदेश देना पड़ा है कि इस मामले में उनके समर्थन को जेब में मानकर नहीं चला जाना चाहिए। जहां बिहार में, एक प्रमुख मुस्लिम मंच ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की घोषणा कर, उस राज्य में नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया, जहां अगले छः महीने के अंदर-अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इस दबाव से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरह, संबंधित मुस्लिम मंच के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई और मुसलमानों के प्रति अपनी वफादारी के आम प्रदर्शन के दुहरे हथियार आजमाए हैं, इसकी चर्चा हम किसी और मौके पर करेंगे।

चीन में तेजी से आगे बढ़ रहा है दिमाग में चिप डालने का प्रोजेक्ट

एक चीनी रिसर्च संस्थान और एक टेक कंपनी ने तीन मरीजों के दिमाग में एक ब्रेन चिप सफलतापूर्वक डाल दी है. साल के अंत तक 13 मरीजों में चिप डालने का लक्ष्य पूरा हो गया तो वो इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक से आगे निकल जाएंगे.

बीजिंग में स्थित चाइनीज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च (सीआईबीआर) और न्यूसाइबर न्यूरोटेक की इस चिप का नाम है बेनाओ नंबर वन. सीआईबीआर के निदेशक और न्यूसाइबर के मुख्य वैज्ञानिक लुओ मिनमिन ने बताया कि पिछले एक महीने में तीन मरीजों में यह चिप लगा दी गई है.

साल के अंत तक 10 और मरीजों में चिप लगाने का लक्ष्य है. सरकारी कंपनी न्यूसाइबर की महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ा ह्यूमन ट्रायल करने की है. एक टेक सम्मेलन के इतर पत्रकारों से बात करते हुए मिनमिन ने कहा, "अगले साल नियामक स्वीकृति मिलने के बाद हम औपचारिक क्लीनिकल ट्रायल करेंगे जिसमें करीब 50 मरीज शामिल होंगे."

अमेरिकी कंपनियों से लोहा

मिनमिन ने फंडिंग या ट्रायल कब तक चलेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी. लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स की गति बढ़ा देने की वजह से मुमकिन है कि बेनाओ नंबर वन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों वाला ब्रेन चिप बन जाएगा. यह दुनिया की अग्रणी ब्रेन चिप कंपनियों से लोहा लेने की चीन की दृढ़ता को रेखांकित करता है.

इस समय इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है अमेरिका की सिन्क्रॉन, जिसके निवेशकों में जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे अरबपति शामिल हैं. सिन्क्रॉन 10 मरीजों में ब्रेन चिप डाल चुकी है, जिनमें से छह अमेरिका में हैं और चार ऑस्ट्रेलिया में.

ब्रेन इम्प्लांट का कमाल का असर

मस्क की न्यूरालिंक के पास इस समय तीन मरीज हैं. न्यूरालिंक ऐसे वायरलेस ब्रेन चिप पर काम कर रही है जिसे सिग्नल की गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है. जबकि उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां सेमि-इनवेसिव चिप पर काम कर रही हैं जिसे दिमाग की सतह पर रखा जाता है.

मथुरा-काशी से जुड़ी नई मुहीम का आह्वान

-ललित गर्ग-

हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दीं। इसीलिये विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने 1984 में तीन मंदिरों की बात की थी, जिनमें में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर बन चुका है। इसके बाद कई लोगों को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके अन्य सहयोगी संगठन इससे संतुष्ट हो चुके हैं और काशी व मथुरा के विषय को जैसे उन्होंने त्याग दिया है या भूला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश किए जाने से कुछ ही घंटे पहले संघ के सरकार्यवाह एवं महामंत्री दत्तात्रेय होसबाले ने काशी ज्ञानवापी और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलनों-कार्यक्रमों में संघ के स्वयंसेवकों को न रोकने की बात कह कर एक नई मुहीम के आह्वान का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे दिया है, जिसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। पिछले कुछ समय से इनको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन संघ के इस मुद्दे पर छाये धुंधलको को हटाते हुए अपने नये बयान से ऊर्जा का संचार किया है। भले ही इससे राजनीति गमार्ये, लेकिन हिन्दू आस्था को इससे खुशी मिली है।

संघ की कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका विक्रमा को दिए इंटरव्यू में होसबाले ने साफ कर दिया कि उस समय यानी 1984 में विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने तीन मंदिरों की बात की थी। इसलिए अगर संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। साफ है, इस बयान के बाद इन मथुरा-काशी दोनों स्थलों से जुड़े विवाद और इनके आंदोलनों को एक नई ऊर्जा, इन मन्दिरों के जीर्णोद्धार, स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करने में सफलता मिलेगी। इससे एक बार फिर भाजपा की ताकत बढेगी एवं हिन्दुओं को एकजुट करने का वातावरण बनेगा। बिहार में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2027 की शुरूआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में जातिगत गणना और आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन दोनों चुनावों में काशी और मथुरा बड़ा मुद्दा बने, तो कोई आश्चर्य नहीं है। दोनों मन्दिर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के दो छोरों पर स्थित हिंदुओं के दो बड़े पवित्र एवं पावन धर्मस्थल हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण आस्था-स्थल हैं, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। दोनों मंदिर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और करोड़ो भक्तों को आकर्षित करते हैं, दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा हैं और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दशार्ते हैं।

काशी में विश्वनाथ और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार केवल भौतिक संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं है-यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार को पुनर्जीवित करने एवं आहत हिन्दू आस्था पर मरहम लगाने का आह्वान है। सनातन धर्म की शाश्वत विरासत के प्रतीक ये मंदिर आक्रमणकारियों के सदियों के हमलों के बावजूद हिंदुओं की दृढ़ता और भक्ति के प्रमाण हैं। इन पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करना हमारे पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करने, हमारी विरासत को संरक्षित करने और हमारी समृद्ध परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मंदिरों के बारे में सच्चाई सबके सामने है, लेकिन ये मामले अनसुलझे हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के ये स्थल लंबी अदालती लड़ाई के बावजूद अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

दत्तात्रेय होसबले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना सही नहीं है। भले ही पिछले साल दिसंबर में मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवाद को शांत करने का उन्होंने यह प्रयास किया था। लेकिन काशी और मथुरा भी उसमें शामिल रहे हो, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? होसबले ने इस साक्षात्कार में गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने, युवाओं में संस्कृति के संरक्षण और देशी भाषाओं की सुरक्षा जैसे समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भाषा नीति पर होसबाले ने त्रिभाषी दृष्टिकोण का समर्थन किया और इसे 95 प्रतिशत भाषाई विवादों का समाधान बताया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनमें शिक्षित लोगों के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

होसबोले ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि वैश्विक भूराजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यदि भारत में हिंदू समाज मजबूत और संगठित नहीं है, तो केवल ह्यअखंड भारतह्न के बारे में बोलने से परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत की खोज में लगे रहने से समाज अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना, युवाओं में मूल्यों का संचार करना तथा संस्कृति और भाषाओं को संरक्षित करना। निश्चित ही होसबले के बोल से जहां हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा को बल मिला है, वहीं राष्ट्रीयता भी मजबूत होती हुई दिख रही है। संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए की गई थी। हमारी सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो धर्म, अहिंसा और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थी उपनिवेशवाद के शोर में अपनी आवाज खो न जाये, हिन्दू समाज पर रह-रह हो रहे हमले रूके, हिन्दू एवं सनातन संस्कृति को सलक्ष्य कुचलने के प्रयास विराम पाये-इन जटिल स्थितियों में भारत के लोगों को एक सांस्कृतिक छत्र के नीचे एकजुट करने की दृष्टि से होसबले ने जगाया है, चेताया है, संगठित होने का आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इन दोनों मन्दिर मुद्दों को नए सिरे से हवा देने की इस कवायद ने संघ विरोधियों एवं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के सामने एक नई गंभीर चुनौती पेश की है। खासकर यह देखते हुए कि अयोध्या की रणनीतिक सफलता ने हिंदुत्व की राजनीति का आधार मजबूत किया है, हिन्दुओं को संगठित किया है।

मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच संघ की तरफ से पहले भी कई बयान आते रहे हैं। ये बयान दशार्ते हैं कि संघ भले ही सीधे-सीधे विवाद से खुद को भले ही अलग रखता हो, वैचारिक रूप से वह इनको पूरा समर्थन देता है। संघ का समर्थन देश को अराजक बनाने का कभी नहीं रहा, उसके सामने बड़ा लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भी है। बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी शक्तियां नए सिरे से सक्रिय होने लगी हैं, उनसे लड़ने की ताकत एवं रणनीति भी संघ चाहता है। संघ सामंजस्यपूर्ण और संगठित भारत के आदर्श को आकार देने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति जैसे आंदोलनों ने भारत के सभी वर्गों और क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से संगठित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा, शासन में सहभागिता से लेकर ग्रामीण विकास तक, राष्ट्रीय जीवन का कोई भी पहलू संघ के स्वयंसेवकों से अछूता नहीं है। सौ वर्षों की संघ यात्रा हिन्दू एकता, सामंजस्यपूर्ण और एकजुट भारत के भविष्य के संकल्प के साथ-साथ काशी-मथुरा के मुद्दे से भी जुड़ी है। हिंदुओं को बचाने और उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ देश सेवा में तत्पर करने के लिये उनकी आस्था एवं अस्तित्व पर लगे घावों को तो भरना ही होगा।

भाजपा में मोदी का विकल्प नहीं

– अरविन्द मोहन

दूसरे खेमे के नेता भाजपा और मुल्क को संभालकर आगे ले जा सकते हों इसमें उनके मुट्ठी भर दीवाने समर्थकों को छोड़कर किसी को भरोसा नहीं है। औरंगजेब के मकबरे के सवाल पर फड़नवीस और संभल के सवाल पर योगी सरकार के व्यवहार से यह साबित हुआ है कि ये नेता चाहे जितना फड़फड़ाएं, मोदी जी का विकल्प नहीं बन सकते।

नए संवत्सर की शुरूआत पर गुड़ीपड़वा के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री की भेंट का इंतजार बहुत लोगों को था लेकिन जो आधिकारिक बातें निकालकर आईं उनसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार समेत की बड़े मसलों पर इन दो शीर्षस्थ लोगों के बीच कोई निर्णयात्मक बात हुई। इस बीच अगर शिव सेना के संजय राऊत प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी वाली बहस न छेड़ते तो बातचीत का मसला न्यूज के हिसाब से फीका होकर एक किनारे लग गया होता। संजय राऊत से महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड़नवीस बहस में उतरे और यह कहा कि न तो भाजपा को कोई उत्तराधिकारी चाहिए और न इस मसले पर कोई चर्चा हुई। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। उनके अनुसार 75 वर्ष पर सक्रिय राजनीति से अलग होने का फैसला प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता और अगले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही अगुआई करेंगे। संजय राऊत 75 वर्ष वाले मसले को उठाने के साथ फड़नवीस बनाम नितिन गडकरी जैसे सवालों को भी छेड़ रहे थे जो महाराष्ट्र और संघ परिवार की राजनीति के लिए काफी महत्व का है। लेकिन गौर से देखेंगे तो मोदी के उत्तराधिकार और भाजपा के अगले अध्यक्ष का सवाल पूरे मुल्क की राजनीति के हिसाब से काफी बड़ा है। अब ऐसा भी नहीं है कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री माइक/कैमरा लगाकर सारी चर्चा करते और हम आप सभी उनकी बातचीत और भाव भंगिमा को सीधे देख सुनकर जान जाते। ऐसा होता नहीं है। पर जिस तरह मोदी जी ने भाजपा के अपने से पुराने नेताओं की जमात को 75 पार के नाम पर सिरे से दरकिनार कर दिया उससे यह उत्सुकता तो होनी ही है कि उनका 75 पूरा होने पर क्या होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा साफ मसला भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लोक सभा चुनाव के पहले यह कहना था कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। वह खुद से सक्षम बन चुकी है। संयोग से उसके बाद उनका कार्यकाल भी खत्म होना था और चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब भी रहा। सो जब नई सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और नया अध्यक्ष चुने जाने तक कामचलाऊ अध्यक्ष के रूप में काम किए जा रहे है।

अब साल नजदीक आ रहा है और भाजपा नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जो बातें छन-छन कर सामने आती रहीं उनके अनुसार इसमें संघ द्वारा अपनी पसंद का आदमी लाना बड़ी वजह है जिससे साबित हों कि भाजपा अभी भी संघ से अलग नहीं है। दूसरी और व्यावहारिक बात भाजपा के कमजोर होने से संघ का हौसला बढ़ना है। और तब से यह काफी प्रचारित हुआ है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा ने संघ के सहारे ही हारती बाजी को पलटा है।

इस लेखक की तरह काफी सारे लोग होंगे जिनकी दिलचस्पी भाजपा और संघ के संबंधों में किसके ऊपर और किसके नीचे होने में नहीं है। और यह गलतफहमी भी नहीं रखनी चाहिए कि कभी संघ और भाजपा जुदा होने या एक दूसरे का नुकसान करने जैसी स्थिति में आएंगे। पर हमारी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी में जरूर है और इसका उनके 75 साल का होने से भी कोई मतलब नहीं है।

अश्लील और कानफोड़ू गानों से करें परहेज

– डॉ. सत्यवान सौरभ

शादी एक खास अवसर होता है, जो दो परिवारों की सांस्कृतिक, पारिवारिक और भावनात्मक दुनिया को जोड़ता है। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है, जिसमें भावनाओं, संस्कारों और परंपराओं का आदान-प्रदान होता है। संगीत इस आयोजन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका चयन बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। केवल मस्ती और डांस तक सीमित न होकर संगीत को हमारे मूल्यों, रिश्तों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

गानों का हमारी भावनाओं और मूल्यों से संबंध

शादी में बजने वाले गाने रिश्तों की गरिमा, परिवार की भावनाओं और संस्कृति का आदान-प्रदान करते हैं। गानों के बोल और धुनों का असर हमारे मनोबल और शादी के समग्र अनुभव पर पड़ता है। शादी एक पारिवारिक आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न आयु समूहों के लोग उपस्थित होते हैं। माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची और छोटे बच्चे भी समारोह में होते हैं। ऐसे में गानों के बोल शालीन और मर्यादित होने चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जैसे कि, जब हम शादी के सादे और गंभीर समारोहों में भाग लेते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एक गहरे बंधन का प्रतीक है, और इस समय का संगीत वही होना चाहिए जो इस सच्चाई को सम्मानित करे। शादी का संकल्प जीवनभर के लिए होता है। यह एक ऐसा वचन होता है जिसमें दोनों पक्षों का प्यार, विश्वास और समर्पण शामिल होते हैं। ऐसे में गाने भी ऐसे होने चाहिए जो प्रेम, रिश्ते और परस्पर सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करें। ब्रेकअप या धोखा पर आधारित गाने, जैसे "चन्ना मेरेया" या "भुला दूंगा", इस अवसर के लिए सही नहीं होते। ये गाने शादी के संकल्प के साथ मेल नहीं खाते हैं।

हर शादी की अपनी संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं। विशेषकर भारतीय शादियों में पारंपरिक संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। ऐसे में, गानों के चयन में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं को ठेस न पहुंचाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि शादी एक विशेष धार्मिक रीति से हो रही है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगीत इस परंपरा के अनुरूप हो। शादी एक उत्सव होता है, और संगीत का मुख्य उद्देश्य इस खुशी को बढ़ाना है। जो गाने उत्साह और खुशी से भरे होते हैं, वे इस अवसर को और खास बना सकते हैं। इसके विपरीत, उदास या नकारात्मक गाने जैसे "तू जो नहीं", "तुम ही हो" आदि माहौल को फीका कर सकते हैं। संगीत को चुनते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हर किसी के मन को खुशी और सकारात्मकता दे। शादी के संगीत का चयन करते समय यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि हम उन गानों से बचें जो अश्लील, द्विअर्थी या असंवेदनशील हों। शादी का माहौल पवित्र और पारिवारिक होता है, और इसलिए हमें उन गानों से बचना चाहिए जो भाषा या भावनाओं से मयार्दा लांघते हों। उदाहरण के तौर पर, "मुन्नी बदनाम" और "शीला की जवानी" जैसे गाने इस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं होते। शादी एक प्रेम और वचन का उत्सव है, और ऐसे गाने जो ब्रेकअप, धोखा या अस्थिर रिश्तों पर आधारित होते हैं, जैसे "चन्ना मेरेया" या "भुला दूंगा", शादी के माहौल के अनुकूल नहीं होते। शादी के समय यदि गाने नशे या अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, तो यह माहौल के अनुरूप नहीं होते। "दारू देसी", "लुंगी डांस", और "माई ड्रिंकिंग" जैसे गाने शादी के गरिमामय माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ गाने जो केवल तेज आवाज और शोर से भरे होते हैं, जैसे कि अत्यधिक बेस वाले गाने या ऊख ट्रैक्स, वे कभी-कभी माहौल को कष्टकारी बना सकते हैं। इनसे बचने के लिए संगीत का चयन इस तरह किया जाना चाहिए कि हर कोई उसे आसानी से सुन सके और उसका आनंद ले सके। हमारी शादी में सभी वर्गों और समुदायों के लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक या जातिगत भावनाओं को आहत करने वाले गानों से बचना चाहिए। इन गानों से बचने के लिए यह जरूरी है कि गानों का चयन एक समानता, सम्मान और प्रेम को व्यक्त करें।

कैसे बनाएं संतुलित प्लेलिस्ट?

संतुलित और विविधतापूर्ण प्लेलिस्ट बनाने के लिए कुछ विशेष टिप्स का पालन किया जा सकता हैः शादी में दूल्हा-दुल्हन के साथ-साथ परिवार और दोस्तों की पसंद का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। प्लेलिस्ट में ऐसे गाने शामिल करें जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुखद हो। गाने हमेशा मधुर और मेलोडियस होने चाहिए। इस तरह के गाने न केवल कानों को अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि वे दिलों को भी जोड़ते हैं। शादी के इस खास दिन पर रोमांटिक गाने, जैसे "तुम ही हो", "तुम जो आए" आदि, माहौल को और भी खास बना सकते हैं। गानों का चयन इस तरह करें कि वे शालीनता और गरिमा का प्रतीक हों। शादी एक गंभीर और सम्मानजनक अवसर है, और इस पर कोई भी गाना जो शब्दों में शालीनता को न दिखाए, उसे सूची से हटा दिया जाना चाहिए।

हर रस्म के लिए सही संगीत का चयन करें। जयमाला के लिए रोमांटिक और भावुक गाने, डांस फ्लोर के लिए एनर्जेटिक ट्रैक, और विदाई के समय पर भावनात्मक धुनें इस दिन को और भी यादगार बना सकती हैं। शादी में पारंपरिक भारतीय संगीत, सूफी गाने, और लोकगीत भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के गाने शादी के पारंपरिक और सांस्कृतिक वातावरण को और अधिक जीवंत बना सकते हैं। अगर बजट अनुमति देता है, तो लाइव बैंड या सूफी गायन को शामिल करना एक अच्छा विचार हो सकता है। लाइव संगीत एक अलग प्रकार की आत्मीयता और जुड़ाव उत्पन्न करता है जो डीजे संगीत से नहीं हो सकता।

शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है

शादी केवल एक उत्सव नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा होती है। संगीत, जो हमारे दिलों और दिमागों को जोड़ता है।

बांग्लादेश में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर 12 घंटे में दो हादसे, 10 की मौत, 27 घायल

ढाका। बांग्लादेश के ढाका-चटगांव राजमार्ग पर लगभग 12 घंटों के दौरान दो सड़क हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। आज सुबह हुए हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों में से किसी की भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, आज सुबह करीब सात बजे चटगांव के लोहागरा उप जिला में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर एक यात्री बस और एक मिनी बस के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। लोहागरा पुलिस थाने के प्रभारी आरिफुर रहमान ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। यह हादसा चुंटी राजमार्ग खंड के जंगलिया इलाके में हुआ। रिलैक्स परिवहन की बस की कॉक्स बाजार जा रही एक मिनी बस से टक्कर हो गई। मिनी बस के सात यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी शव लोहागरा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इसी राजमार्ग पर करीब 6:30 बजे कुमिल्ला के चंदिना उप जिला में एक बस के बिजली के खंभे और पेड़ से टकरा जाने से तीन यात्रियों (सभी पुरुष) की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। मीडिया में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आने के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से संपर्क किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉन अखबार के अनुसार, हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय या पीपीपी की ओर से अपने सह अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुबह मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति जरदारी को नवाबशाह से लाए जाने के बाद कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी कुछ जांचें की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। प्रेस सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनका हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच, सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन को फोन कर जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। अक्टूबर 2024 में विमान से उतरते समय राष्ट्रपति के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। गिरने के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

नेपाल में राजशाही के पक्ष में हुए आंदोलन के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी कमी

काठमांडू। नेपाल में राजशाही के पक्ष में पिछले एक महीने से लगातार हो रहे आंदोलन के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक नेपाल में पर्यटकों का सीजन रहता है लेकिन मार्च महीने की शुरुआत में ही पर्यटकों की संख्या में कमी आने से पर्यटन क्षेत्र पर इसका असर हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च के महीने में जितने पर्यटकों के आने की अपेक्षा की गई थी, उसके मुताबिक पर्यटकों का आगमन नहीं हो पाया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक राज जोशी ने बताया कि पिछले एक महीने से काठमांडू सहित देश की कई स्थानों में चल रहे आंदोलन के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण पश्चिमी देशों के तरफ से जारी ट्रैवल एडवाइजरी के कारण विदेशी पर्यटक नेपाल आने से बच रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने मार्च महीने का तथ्यंक सार्वजनिक किया है जिसके मुताबिक मार्च महीने में सिर्फ एक लाख दस हजार पर्यटक ही नेपाल आए हैं जो कि वर्ष 2024 के मार्च महीने की तुलना में काफी कम है। पर्यटन बोर्ड के द्वारा जारी बयान के मुताबिक मार्च 2024 में जहां 1,70,000 पर्यटक नेपाल आए थे, वहीं इस वर्ष मार्च महीने में सिर्फ एक हजार पर्यटक ही आ पाए हैं।

खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर को समिति के फैसले पर इस्तीफा देना चाहिए : इमरान खान

रावलपिंडी,। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि यदि पार्टी समिति कोई निर्णय लेती है, तो खैबर पख्तूनख्वा (केपी) के स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए। यह जानकारी पीटीआई नेता आजम स्वाती ने दी। आजम स्वाती ने मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद जेल से बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीटीआई संस्थापक ने सलमान अक़रम राजा की पार्टी के प्रति निष्ठा पर भरोसा जताया और कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नहीं जाएंगे। स्वाती ने बताया कि उन्होंने इमरान खान को मानसेहरा में हो रही कथित भ्रष्टाचार की घटनाओं से अवगत कराया, जिस पर खान ने कहा कि पार्टी समिति को इस मुद्दे को आगे लाना चाहिए। स्वाती ने आगे कहा कि इमरान खान ने केपी के पीटीआई अध्यक्ष अकबर द्वारा की गई नियुक्तियों को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अकबर पार्टी नेतृत्व के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

भूकंप के पांच दिन बाद इमरात के मलबे से एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया

एजेंसी

यांगून । म्यांमार के नेपीडॉ में बुधवार को एक ढही हुई होटल की इमारत के मलबे से 26 वर्षीय एक होटल कर्मचारी को बचा लिया गया। राज्य प्रशासन परिषद की सूचना टीम के मुताबिक, देश में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के पांच दिन बाद व्यक्ति को बचाया गया। सूचना टीम ने बताया कि मलबे में दो लोग फंसे हुए थे। म्यांमार अग्निशमन सेवा विभाग और तुर्की की बचाव टीमों ने एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। होटल में अभियान मंगलवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:00 बजे शुरू हुआ और बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 00:30 बजे व्यक्ति को बचा लिया गया। समाचार एजेंसी के अनुसार, फंसे हुए बाकी लोगों को खोजने और बचाने के प्रयास जारी हैं।भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,719 हो

गई, लगभग 4,521 लोग घायल हुए और 441 अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री मिन आंग ह्लाइंग ने यह जानकारी दी। इस बीच, म्यांमार के जुंटा के प्रमुख आंग ह्लाइंग ने जातीय सशस्त्र संगठनों (ईएओ) के युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया और सैन्य अभियान जारी रखने की घोषणा की। ह्लाइंग ने कहा, 'कुछ जातीय सशस्त्र समूह अभी सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वे हमलों की तैयारी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। चूंकि यह आक्रामकता का एक रूप है, इसलिए सेना जरूरी रक्षा अभियान जारी रखेगी। म्यांमार नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वक्त में जब वैश्विक ध्यान भूकंप के विनाश और मानवीय सहायता भेजने पर केंद्रित है, म्यांमार की सेना ने देश भर में प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हैं। हमलों पर चिंता जताते हुए, अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार की सैन्य सरकार को भूकंप पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता तक तत्काल, निर्बाध पहुंच की अनुमति देनी चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाले प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।

नेपाल-थाईलैंड प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

एजेंसी

काठमांडू। थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगट्रान शिनावात्रा के बीच बुधवार को बैंकाक में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।बैंकाक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बैठक में शामिल हुई नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउवा ने कहा कि थाईलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापना के 65 साल के बाद पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा होना अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने एक सरकारी इमारत में प्रधानमंत्री ओली का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक के बाद संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्री डॉ. आरजू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इसी तरह दोनों देशों के गैर-सरकारी और व्यावसायिक संगठनों के बीच छह अलग-अलग समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक दूसरे देशों को पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान करने पर जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपने थाई समकक्ष के साथ आज आयोजित दोपहर के भोजन में भाग लेंगे और आज ही थाईलैंड के राजा महा वाजिरालोंगकोर्न के साथ शिष्टाचार बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ओली 4-5 अप्रैल को बैंकाक में ही आयोजित बीमस्टेक शिखर सम्मेलन में सहभागी होने वाले हैं।

यमन के होदेइदाह शहर पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों में तीन की मौत

एजेंसी

सना । हूती मीडिया और निवासियों ने बताया कि यमन के पश्चिमी प्रांत होदेइदाह शहर पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम तीन लोग मारे गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हुए हमलों में मध्य होदेइदाह के मंसूरिया जिले में एक 'जल परियोजना और उसकी इमारत' को निशाना बनाया गया। जिले के निवासियों ने सिन्हुआ को बताया कि मलबे में दबे जीवित लोगों की तलाश जारी है। समाचार एजेंसी ने हूती मीडिया के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों हज्जाह और सादा में कई स्थानों पर हवाई हमले किए। इससे पहले दिन में, हूती मीडिया ने उत्तरी यमन में कई स्थानों पर अमेरिकी हवाई हमलों की सूचना दी, जिसमें राजधानी सना के पश्चिम में बानी मातर जिले में माउंट नबी शुअयब और सादा शामिल हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ईरान समर्थित हूती, जो उत्तरी यमन के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखते हैं, 2014 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से लड़ रहे

हैं। अमेरिकी सेना ने 15 मार्च से उत्तरी यमन में हूती के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, ताकि इस समूह को अमेरिकी नौसेना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर हमला करने से रोका जा सके। पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमले लंबे समय तक जारी रहेंगे।इससे पहले मंगलवार को हूती समूह ने बताया कि अमेरिकी सेना ने पिछले कई घंटों में यमन के उत्तरी सना और सादा प्रांतों में उसके ठिकानों पर 22 हवाई हमले किए हैं।

हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी द्वारा प्रसारित एक संक्षिप्त बयान के अनुसार, भोर में पांच हवाई हमले सना के दक्षिण-पूर्व में सानहान जिले के जरबन क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए, जबकि दो अन्य हमले राजधानी के पश्चिम में बानी मातर जिले में किए गए। बयान में आगे बताया गया कि समूह के गढ़ सादा पर रात भर में 15 अमेरिकी हवाई हमले किए गए, लेकिन टारगेट किए गए क्षेत्रों का खुलासा नहीं किया गया।

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी शरणार्थियों में से तीन को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया

एजेंसी

काठमांडू। अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार करते हुए उन सभी को वापस नेपाल भेज दिया है। इनमें से तीन भूटानी शरणार्थियों को नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका जाने से पहले ये सभी 10 लोग नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।

नेपाल के झापा जिले के एसपी मिलन केसी ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने वाले 10 में से तीन भूटानी नागरिकों को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता लगा है कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद भूटान सरकार ने उन्हें अपने यहां रखने से इनकार कर दिया जिसके बाद वो भारत के रास्ते नेपाल में दोबारा आ गए हैं। अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नेपाल में रह रहे

भूटानी शरणार्थियों को ले जाया गया था लेकिन अब उनको अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। बीते सोमवार को अमेरिका से दिल्ली होते हुए थिंपू भेजे गए 10 नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार किया है नेपाल में पुलिस नियंत्रण में लिए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद उन्हें जब सोमवार को थिंपू एयरपोर्ट पर उतारा गया तो वहां की सरकार ने प्रति व्यक्ति 30 हजार रुपये देकर भूटान से विदा कर दिया। नेपाल में गिरफ्तार किए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि चूंकि वो नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविर से अमेरिका गए थे इसलिए भूटान सरकार ने उन्हें दोबारा शरणार्थी शिविर में रहने के लिए भेजा है।

अमेरिकी सीनेटर ने नॉन-स्टॉप भाषण देकर बनाया नया रिकॉर्ड, संसद में 25 घंटे से भी ज्यादा बोले डेमोक्रेट कोरी बुकर

एजेंसी

न्यूयॉर्क । सीनेट में लगातार 25 घंटे से अधिक समय तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते हुए एक डेमोक्रेट सीनेटर ने कांग्रेस में सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाया है। सीनेटर कोरी बुकर ने सोमवार शाम को अपना भाषण शुरू किया और मंगलवार शाम को इसे समाप्त किया। बिना किसी ब्रेक के, एक व्याख्यान-पीठ पर खड़े होकर दिए गए भाषण में असाधारण सहनशक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीनेट के उस नियम का लाभ उठाया जो सीनेटरों को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और उनकी छवि बनाने के लिए समय सीमा के बिना बोलने की अनुमति देता है। उन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए असफल रूप से भाग लिया और अंततः पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया। साथी डेमोक्रेट्स ने नियमों के तहत अनुमति के अनुसार उनसे सवाल भी पूछे। उन्होंने 1957 में एक नस्लवादी सीनेटर स्ट्रोम थरमंड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने नागरिक अधिकार अधिनियम को पारित होने से रोकने के लिए सीनेट में 24 घंटे और 18 मिनट तक का भाषण दिया था, जिसने अमेरिकियों के लिए मतदान के अधिकार की गारंटी दी। थरमंड के भाषण समाप्त होने के कुछ घंटों बाद सीनेट ने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार कानून पारित कर दिया और राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने इसे कानून में हस्ताक्षरित कर दिया। जब उन्होंने अपना मैराथन भाषण दिया, तब थरमंड एक डेमोक्रेट थे। 1964 में थरमंड रिपब्लिकन पार्टी में चले गए, तब तक दोनों पार्टियों ने अपनी नीतियां बदल ली थीं। बुकर ने थरमंड के बारे में कहा, 'उनसे नफरत करना गलत है,' और आगे कहा, 'मैं उनके भाषण के कारण यहां नहीं हूं। मैं उनके भाषण के बावजूद यहां हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि वे जितने शक्तिशाली थे, लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अपने भाषण में कई जगहों पर नागरिक अधिकार नेता जॉन लुईस का हवाला देते हुए, उन्होंने अंत में अपने शब्दों को दोहराया, 'अच्छी परेशानी में पड़ो, जरूरी परेशानी में पड़ो, और अमेरिका की आत्मा को बचाने में मदद करो।'थरमंड के विपरीत, बुकर कानून में देरी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल ट्रंप के विरोध में ही खड़े थे। 55 वर्षीय बुकर स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय के एथलीट रहे हैं। वे अमेरिकी फुटबॉल चैंपियन थे और विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने रोड्स स्कॉलरशिप अर्जित की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और येल से कानून की डिग्री प्राप्त की। न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर ने ट्रंप की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या अमेरिकी अब बेहतर स्थिति में हैं या ट्रंप के पदभार संभालने से 72 दिन पहले थे? उन्होंने आगे कहा, 'अब कीमतें अधिक हैं, शेयर बाजार जहां कई अमेरिकी अपनी सेवानिवृत्ति निधि रखते हैं, नीचे चला गया है और उपभोक्ता विश्वास घटा है।उन्होंने कहा कि कीमतें कम करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के बजाय, ट्रंप टैरिफ बढ़ाने जैसी नीतियों का पालन कर रहे हैं जो केवल कीमतों को बढ़ाएंगे, जबकि कनाडा पर हमला करते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं।

ट्रंप और मस्क को बड़ा झटका, विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट समर्थित जज क्रॉफोर्ड विजयी

एजेंसी

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज हर जुबान पर जज सुसान क्रॉफोर्ड की जीत की चर्चा है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी डेमोक्रेटिक समर्थित उम्मीदवार जज सुसान क्रॉफोर्ड के विस्कॉन्सिन राज्य के सुप्रीम कोर्ट की दौड़ जीतने की सुर्खी है। इस दौड़ के लिए हुए चुनाव में वो जीत गई हैं। उन्होंने इसके लिए मतदाताओं का आभार जताया है। मीडिया में इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी अरबपति एलन मस्क के लिए सबसे तगड़ा झटका बताया गया है। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तीन महीने से भी कम समय में डेन काउंटी में एक उदार सर्किट कोर्ट जज क्रॉफोर्ड ने रूढ़िवादी उम्मीदवार ब्रैड शिमेल को हरा दिया। वो वौकेशा काउंटी के जज हैं। उन्हें चुनाव अभियान के अंतिम चरण में ट्रंप का खुला समर्थन प्राप्त था। क्रॉफोर्ड की जीत को विस्कॉन्सिन और देशभर में डेमोक्रेट के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। मतदाताओं ने राष्ट्रपति के पसंदीदा उम्मीदवार को पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा में हरा दिया। एलन मस्क ने इस जनमत संग्रह में अपनी निजी संपत्ति के लाखों डॉलर फूंक दिए। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी न्यायिक प्रतियोगिता बन गई। मंगलवार रात मैडिसन की विजय रैली में क्रॉफोर्ड ने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विस्कॉन्सिन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर अभूतपूर्व हमले को विफल कर दिया। विस्कॉन्सिन के लोगों ने साबित कर दिया कि अदालतें बिक्री के लिए नहीं हैं।

पूर्व राजा पर भड़के पीएम ओली, कहा - दोषी पाए गए तो करना होगा सजा का सामना

एजेंसी

काठमांडू । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले राजशाही समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 28 मार्च की हिंसा में दोषी पाए जाने पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को भी नहीं बख्शा जाएगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बयान के जरिए शाह पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। ओली ने कहा कि पूर्व राजा समेत आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा से छूट नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सवाल किया, क्या सिंहासन वापस पाने की आकांक्षा रखने वालों को विरोध और उसके परिणामों पर अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से नहीं बतानी चाहिए? ओली ने संसद में कहा, उन्हें (पूर्व राजा को) किसी भी तरह से

सजा से छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और राजशाही को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 28 मार्च की घटनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इन भयावह कृत्यों के दोषियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के सांसदों को संविधान को खत्म करने से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे चार्टर की रक्षा करने के लिए शपथबद्ध हैं। इस बीच, ओली के भाषण ने संसद में आरपीपी के सांसदों के विरोध को भड़का दिया। नेपाल के प्रमुख दैनिक काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी प्रमुख राजेंद्र लिंगडेन ने 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से ही रिपब्लिकन पार्टियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सदन की बैठक में बोलते हुए, आरपीपी नेता लिंगडेन ने चेतावनी दी कि अगर लोग चाहें तो रिपब्लिकन व्यवस्था को पलटा जा सकता है। उन्होंने कहा, क्या दंगों के लिए केवल प्रदर्शनकारी ही जिम्मेदार थे? क्या स्थिति को नियंत्रण में लेना सरकार का कर्तव्य नहीं था? लिंगडेन ने आगे आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने छतों से एक्सपायर हो चुकी आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। उन्होंने काठमांडू के टिंकुने में हुई घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की।

इजराइल की सेना बमबारी करके दक्षिणी गाजा में घुसी, 17 की मौत

एजेंसी

गाजा पट्टी। इजराइल की सेना (आईडीएफ) रातभर बम बरसाते हुए आज सुबह दक्षिणी गाजा में प्रवेश कर गई। इस बमबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। हमास के कई महत्वपूर्ण ठिकाने पलक झपकते ही मटियामेट हो गए। सेना के दक्षिणी गाजा में घुसने पर इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि देश की सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। अब गाजा पट्टी में व्यापक क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा।

साथ ही आतंकवादी समूह हमास के हमदर्द भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार रक्षामंत्री काट्ज ने आज कहा कि देश की थल और नभ सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। जल्द ही गाजा पट्टी के बड़े भू-भाग पर नियंत्रण कर उसे गाजा पट्टी के तथाकथित बफर जोन में शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इजराइल ने रातभर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आईडीएफ ने क्षेत्र में एक और डिवीजन तैनात किया है। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार, इजराइल की फौज ने राफाह और खान यूनिस में रातभर कहर बरपाया है। आज सुबह इजराइल के सैनिक राफाह में आगे बढ़ते दिखे। आईडीएफ ने सोमवार को पूरे राफाह क्षेत्र और खान यूनिस के बीच की भूमि के एक बड़े क्षेत्र के लिए निकासी की चेतावनी जारी की थी। अब तक इस क्षेत्र में शांति रही है। कैट्ज ने कहा कि सेना हर हाल में हमास के आतंकवादियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करेगी।

इस बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि बुधवार भोर खान यूनिस और नुसेरात शरणार्थी शिविर में हुए इजराइली हवाई हमलों में बच्चों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए। हमास नियंत्रित गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान पुनः शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में 1,042 लोग मारे गए हैं।

दरअसल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास नेताओं के सामने सशर्त गाजा छोड़ने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि हमास अगर बिना खूनखराबे के बंधकों को रिहा कर दे तो उसके लड़ाकों को गाजा को खाली करने से नहीं रोका जाएगा। गाजा पट्टी में छिड़े युद्ध के दौरान मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से संघर्ष विराम कराने और इजराइली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

नेपाल के सबसे बड़े ड्राई पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय कंपनी को सौंपी गई

काठमांडू। बीरगंज रक्सौल सीमा पर नेपाल के सबसे बड़े ड्राई पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भारत की निजी कंपनी को सौंपी गई है। अब तक इसका संचालन भारतीय रेलवे के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा था। अब इसका संचालन भारत की निजी कंपनी प्रिंसटन मेगा लॉजिस्टिक पार्क की तरफ से किया जाएगा। नेपाल के सभी ड्राई पोर्ट के संचालन की देख-देख करने वाली सरकार की इंटर मॉडल यातायात विकास समिति के कार्यकारी निदेशक आशीष गजवेल ने बताया कि जुलाई, 2025 से 5 वर्षों के लिए बीरगंज ड्राई पोर्ट संचालन की जिम्मेदारी प्रिंसटन मेगा लॉजिस्टिक पार्क को दी गई है। भारत की कंपनी को अगले 5 वर्ष के लिए 471 करोड़ रुपये में इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस ड्राई पोर्ट के संचालन का ठेका 333 करोड़ रुपये में दिया गया था। इस वर्ष भी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 450 करोड़ रुपये का टेंडर भरा था, लेकिन भारतीय निजी कंपनी प्रिंसटन ने 471 करोड़ रुपये का टेंडर भरे जाने से इस बार बाजी मार ली है। नेपाल और भारत के बीच आयात-निर्यात के लिए बीरगंज का ड्राई पोर्ट सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार की तरफ से निर्मित इस ड्राई पोर्ट में कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह से सीधी कंटेनर सेवाएं उपलब्ध है।

14,000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, अदालत सुनाएगी राष्ट्रपति यून के महाभियोग पर फैसला

एजेंसी

सोल । संवैधानिक न्यायालय 5 अप्रैल दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग मामले में फैसला सुनाने वाला है। इसे देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। दक्षिण कोरियाई पुलिस ने सोल में लगभग 14,000 कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने पुलिस बलों को 'गैफो' अलर्ट पर रखा है, जो उच्चतम स्तर है और सभी उपलब्ध पुलिस बलों को आपातकालीन स्टैंडबाय पर रखता है। सभी संवैधानिक न्यायालय के जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस संवैधानिक न्यायालय परिसर में घुसने का प्रयास करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी।

यदि यून फैसले के लिए अदालत में उपस्थित होते हैं, तो पुलिस राष्ट्रपति निवास से संवैधानिक न्यायालय तक के मार्ग को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगी और रास्ते में उनके पक्ष या विपक्ष में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अलग करेगी।

महाभियोग केस में फैसले की तारीख की घोषणा के तुरंत बाद ग्वांगह्वामुन स्क्वायर के पास यून विरोधी प्रदर्शनकारियों ने, [जहां वे रात भर धरना दे रहे थे], इसका स्वागत किया और निलंबित राष्ट्रपति को तत्काल पद से हटाने के नारे लगाए। लॉयर्स फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अध्यक्ष यून बोक-नाम, [जिन्हें मिनब्यून के नाम से भी जाना जाता है], ने बताया कि यून के महाभियोग के फैसले की तारीख बहुत देर से आई है, लेकिन फिर भी यह राहत की बात है। हालांकि, संवैधानिक न्यायालय के पास यून समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कोरियाई और अमेरिकी झंडे लहराते हुए महाभियोग खारिज करो के नारे लगाए।पुलिस ने कथित तौर पर न्यायालय की घोषणा के बाद मंगलवार दोपहर तक संवैधानिक न्यायालय के पास लगभग 3,200 कर्मियों को तैनात कर दिया। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक न्यायालय यदि महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखता है, तो यून को पद से हटा दिया जाएगा। अगर इसे खारिज कर दिया जाता है, तो उन्हें मई 2027 तक अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए बहाल कर दिया जाएगा। यून की कानूनी टीम ने कहा कि फैसले के लिए अदालत में उनकी उपस्थिति अभी भी अनिश्चित है। यून पर मार्शल लॉ लागू करके संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा लेकिन इसने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति यून सुक-योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री हान डक-सू ने उनकी जगह ली लेकिन उनके खिलाफ भी महाभियोग पारित हुआ। इसके बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभालने लगे। हालांकि 24 मार्च को संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया।

भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 50 में जगह बनाई

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 50 में जगह बना ली है। वह अब दुनिया में 47वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इस बीच, स्नेहित सुरवज्जुला ने पहली बार शीर्ष 100 में जगह बनाते हुए 89वां स्थान हासिल किया है। एक मार्मिक मोड़ में, शरत कमल, जिन्होंने प्रतिस्पर्धी टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी, ने विश्व नंबर 80 पर अपने शानदार करियर का समापन किया। अपने अंतिम मैच में कमल पर सुरवज्जुला की जीत ने अनुभवी के करियर का प्रतीकात्मक अंत कर दिया। चेन्नई में डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर में भारत का अभियान रविवार को समाप्त हो गया, जब ठक्कर को पुरुष एकल सेमीफाइनल में फ्रांस के विश्व नंबर 54 थिबॉल्ट पोरेट से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष के रूप में इतिहास रचने वाले ठक्कर ने जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक उच्च-ऊर्जा मैच में कड़ी टक्कर दी। जोशीले प्रयास के बावजूद ठक्कर को अंततः 20 वर्षीय फ्रांसीसी खिलाड़ी ने मात दी, जिसने 12-10, 11-9, 7-11 और 11-7 के स्कोर के साथ जीत हासिल की।

विश्व मुक्केबाजी कप 2025 : लक्ष्य चाहर की हार के साथ भारत ने किया अभियान का आगाज

फ़ोज़ डू इगुआकु (ब्राजील)। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में लक्ष्य चाहर का अभियान 80 किग्रा के शुरुआती मुकाबले में ब्राजील के वांडरले परेरा के सामने 0-5 से निराशाजनक हार के साथ शुरू हुआ।मौजूदा राष्ट्रीय लाइट हैवीवेट चैंपियन चाहर को (स्थानीय समयानुसार) को परेरा के रूप में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, जो 2023 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और पेरिस ओलंपियन हैं। परेरा ने रिंग में चाहर को पछाड़ दिया, जिसमें एक जज को छोड़कर सभी ने उन्हें 30 अंक दिए। ब्राजील के इस खिलाड़ी ने 150 में से 149 का लगभग पूर्ण स्कोर हासिल किया, जबकि चाहर ने 135 अंक हासिल किए। यह हार विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण शुरुआत है, जो कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल होने से पहले फरवरी में विश्व मुक्केबाजी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से अनंतिम मान्यता मिलने के बाद पहला आयोजन है। यह नए शुरू किए गए भार वर्गों के तहत प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय मुक्केबाजों के लिए पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है। छह दिवसीय टूर्नामेंट के दूसरे दिन तीन अन्य भारतीय मुक्केबाज जदुमणि सिंह मंडेंगबाम (50 किग्रा), निखिल दुबे (75 किग्रा), और जुगनू (85 किग्रा) रिंग में उतरेंगे। जदुमनी का सामना ग्रेट ब्रिटेन के एलिस ट्रोब्रिज से होगा, जो क्वार्टर फाइनल में एक मुश्किल मुकाबला होगा। निखिल का मुकाबला स्थानीय मुक्केबाज काऊ बेलिनी से होगा, जबकि जुगनू का मुकाबला फ्रांस के अब्दुलाये ट्रोरे से होगा।

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स फिटनेस के कारण शुरुआती काउंटी मैचों से बाहर

लंदन। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के काउंटी चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबलों में खेलने की संभावना बेहद कम है। डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की। स्टोक्स इस समय हैमस्ट्रिंग की सर्जरी के बाद फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 33 वर्षीय स्टोक्स को पिछले साल दिसंबर में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी थी। यह पांच महीनों में दूसरी बार था जब उन्हें यह समस्या हुई, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। इंग्लैंड को मई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके बाद भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की अहम सीरीज होगी। साल के अंत में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में एशेज के लिए भी उतरना है। डरहम की टीम मई में जिम्बाब्वे टेस्ट से पहले छह काउंटी चैंपियनशिप मैच खेलेगी, लेकिन स्टोक्स के इन मुकाबलों में खेलने की संभावना नहीं है। डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि टीम को सिर्फ स्टोक्स ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स (पैर की चोट) और मार्क वुड (घुटने की चोट) की भी कमी खलेगी। कैंपबेल ने कहा, स्टोक्स, कार्स और वुड का हमारे लिए खेलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। उनकी प्राथमिकता इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से फिट होना है। स्टोक्स ने सर्जरी के अगले ही दिन वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी, जो उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। वह टीम के लिए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं।

धीमी ओवर गति के लिए पाकिस्तान पर लगा जुर्माना

दुबई। पाकिस्तान पर नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गये पहले एकदिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने मोहम्मद रिजवान की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय सीमा में दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाये जाने पर यह जुर्माना लगाया है।आईसीसी मीडिया बयान में कहा गया कि रिजवान ने अपराध और जुर्माना स्वीकार कर लिया है इसलिए इस पर औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई। यह आरोप मैदानी अंपायर क्रिस ब्राउन और पॉल रीफेल, तीसरे अंपायर माइकल गॉफ और चौथे अंपायर वेन नाइट्स द्वारा लगाया गया था।

शार्लेट एडवर्ड्स बनीं इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की नई हेड कोच

एजेंसी

लंदन। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शार्लेट एडवर्ड्स को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। पूर्व इंग्लैंड कप्तान एडवर्ड्स ने अपने देश के लिए 300 से अधिक मैच खेले हैं और अपने 20 साल के क्रिकेट करियर में दो वर्ल्ड कप और पाँच बार एशेज ट्रॉफी जीती है। 2017 में संन्यास लेने के बाद, एडवर्ड्स ने इंग्लिश घरेलू क्रिकेट और वैश्विक टी20 लीगों में कोचिंग की है। उन्होंने दक्षिणी वाइपर, द हंड्रेड में साउदर्न ब्रेव, विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ सफलता हासिल की है।

अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए एडवर्ड्स ने कहा, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के नेतृत्व का फिर से हिस्सा बनने पर मैं बेहद रोमांचित हूं। इस टीम को आगे ले जाना और सफलता की ओर बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए फिर से तीन शेरों (इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का लोगो) को धारण करना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड की कप्तानी करना मेरे

जीवन का अहम हिस्सा रहा है और मैं हमेशा इस टीम और इसकी विरासत के प्रति समर्पित रहूंगी। हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है, और मैं उनके साथ काम करने और उन्हें व्यक्तिगत और टीम स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने आगे कहा, हमारे सामने दो घरेलू सीरीज का त्वरित चुनौती है, जिसके बाद इस साल के अंत में भारत में आईसीसी महिला विश्व कप खेला जाना है। अगले साल इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप भी होगा और इसके बाद 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में महिला क्रिकेट की पहली उपस्थिति होगी। मैं इस टीम के साथ ट्रॉफी जीतने और इसे आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। ईसीबी की डिप्टी सीईओ और इंग्लैंड महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने कहा, जब हमने इस पद के लिए मानदंड तय किए, तो यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि शार्लेट एडवर्ड्स सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके पास अनुभव, जुनून और विशेषज्ञता है, जो इस टीम को सफलता की ओर ले जा सकती है। बतौर हेड कोच उन्होंने अलग-अलग टीमों के साथ बेहतरीन नतीजे दिए हैं। यह उनके निरंतर प्रयास और उच्च मानकों का प्रमाण है। वह एक सिद्ध विजेता हैं, जिन्होंने एक खिलाड़ी और अब कोच के रूप में लगातार सफलता हासिल की है। शार्लेट एडवर्ड्स वर्तमान में हैम्पशायर से ईसीबी में शामिल हो रही हैं। इंग्लैंड महिला टीम की हेड कोच के रूप में उनका पहला मैच 21 मई को वेस्टइंडीज के खिलाफ कैंटरबरी में होगा। इंग्लैंड महिला टीम के नए कप्तान की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में आयकर विभाग के खिलाड़ियों का जलवा

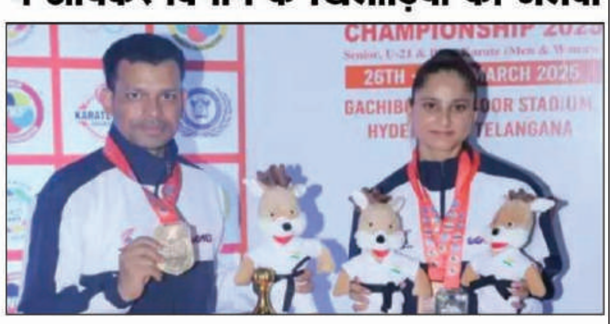

एजेंसी

नई दिल्ली। गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में 26 से 29 मार्च तक आयोजित सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप में आयकर खेल और मनोरंजन क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 31 राज्यों के कराटे खिलाड़ी, एसएससीबी,आईटीबीपी और असम राइफल्स की टीमें शामिल हुईं। आयकर खेल और मनोरंजन क्लब ने एक बयान में कहा कि आयकर विभाग के खिलाड़ी अनिकेत गुप्ता ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। यह विश्व कराटे महासंघ (डब्ल्यूकेएफ)और एशियाई कराटे महासंघ (एकेएफ) की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका 42वां पदक है। खास बात यह है कि अनिकेत लगातार 18 वर्षों से पदक जीतते आ रहे हैं, जो उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। प्रतियोगिता में दीपिका धीमान ने भी शानदार प्रदर्शन किया और दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए। यह डब्ल्यूकेएफ और एकेएफ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी 30वीं पदक जीत है।

वेस्ट इंडीज़ 1975 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा

एजेंसी

नई दिल्ली। वेस्ट इंडीज़ अपनी ऐतिहासिक 1975 विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में 21 जून 1975 को हासिल किया गया था। उस समय इसे 'प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप' कहा जाता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लाइव लॉयड की शानदार सेंचुरी ने वेस्ट इंडीज़ को 17 रन से जीत दिलाई थी और लॉयड ने ट्रॉफी उठाई थी। वेस्ट इंडीज़ के इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन बारबाडोस में होगा, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। मैं विस्तार से तो नहीं जानता, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि हम अपनी उपलब्धियों को मान्यता दे रहे हैं। होल्डिंग, जो 1975 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं थे, 1979 और 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा रहे। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराया था। होल्डिंग ने आगे कहा, सभी अन्य देश अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और हमें भी अपनी कहानी लिखनी

चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए 1975 की विश्व कप जीत वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्षणों में से एक मानी जाती है, जो उनके विश्व क्रिकेट में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के समय पर आई। वेस्ट इंडीज़ का प्रभुत्व अगले दशक तक बना रहा, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई, और तब से वह पूरी तरह से वापस नहीं आ सकी है। सीडब्ल्यूआई के अध्यक्ष डॉ. किशोर शैलो ने हाल ही में मीडिया सम्मेलन में इस आयोजन की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस साल हम 1975 में हुई अपनी पहली विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम आयोजन के अंतिम चरण में हैं, कुछ चीज़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डॉ. शैलो ने स्पोर्ट्समैक्स वेबसाइट को बताया,यह हमारे वार्षिक कैलेंडर का एक प्रमुख हिस्सा होगा। इस जीत के 12 जीवित सदस्य हैं, और हम उनका सम्मान बारबाडोस में होने वाले इस समारोह में करेंगे। यह हमारे लिए एक शानदार आयोजन होगा, साथ ही हम अपनी घरेलू सीरीज का भी इंतजार कर रहे हैं, वर्तमान में जीवित 12 सदस्य हैं: गॉर्डन ग्रीनिज़ (73), अल्विन कालिचरन (76), रोहन कन्हाई (89), क्लाइव लॉयड (80), विव रिचर्ड्स (73), बर्नार्ड जूलियन (75), डेरेक मरे (81), वैनबर्न होल्डर (79), एंडी रॉबर्ट्स (74), कॉलिस किंग (73), लांस गिब्स (90) और मौरिस फोस्टर (81)।

हार के बाद लखनऊ की पिच पर फूटा जहीर खान का गुस्सा, कहा-ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब के क्यूरेटर ने तैयार की हो

एजेंसी

लखनऊ। आईपीएल 2025 में घरेलू मैदान की पिच से परेशान होने वाली टीमों की सूची में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी शामिल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद, अब एलएसजी भी अपने होम ग्राउंड की पिच से निराश नजर आई। टीम के मेंटॉर ज़हीर खान ने अपनी नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो यहां पंजाब का क्यूरेटर काम कर रहा हो। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद ज़हीर खान ने पिच को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मैच के बाद जहीर खान ने कहा, यह थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यह हमारा घरेलू मैदान है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि टीमें अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां क्यूरेटर ने इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे यह पंजाब का क्यूरेटर था। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए भी एक नई जिम्मेदारी

है, लेकिन उम्मीद है कि यह पहला और आखिरी मैच होगा जहां ऐसा हुआ। हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमें अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जहीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने और कप्तान ऋषभ पंत ने पिच को गलत पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए, हम तो वही करेंगे जो क्यूरेटर कहेगा, नहीं? इसे बहाने के रूप में नहीं ले रहे, लेकिन पिछले सीजन में भी हमने देखा कि यहां बल्लेबाजों को दिक्कत होती थी और गेंदबाज हावी रहते थे। लेकिन यह घरेलू टीम के समर्थन की बात है, और हर किसी को इसे समझना चाहिए। ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद कहा कि एलएसजी इस मुकाबले को धीमी पिच पर खेलना चाहती थी, लेकिन मैदान की स्थिति वैसी नहीं थी। एलएसजी ने इस सीजन के अपने तीन में से दो मुकाबले गंवा दिए हैं, और उनका घरेलू रिकॉर्ड अब 15 मुकाबलों में केवल 7 जीत तक सीमित हो गया है। इकाना स्टेडियम में खेले गए इन मैचों में केवल एक बार ही 200 से अधिक का स्कोर बना है, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि पिच टीम की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। जहीर ने कहा,यही तो आईपीएल की चुनौती है, । आपको घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेलना होता है। यह हमारा पहला घरेलू मुकाबला था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। पंजाब ने हमें पूरी तरह से मात दी, और यही खेल की प्रकृति है।

कोपा डेल रे सेमीफाइनलः रूडिगर बने हीरो, रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर फाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद के खिलाफ रोमांचक 4-4 के ड्रॉ के साथ कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बनाई, जिससे उसने कुल 5-4 के स्कोर के साथ सेमीफाइनल जीत लिया। एंटोनियो रूडिगर ने 115वें मिनट में हेडर के जरिए निर्णायक गोल किया, जिससे मैड्रिड अब फाइनल में बार्सिलोना या एटलेटिको मैड्रिड का सामना करेगा। पहले चरण में 1-0 से पिछड़ रही रियल सोसिएदाद ने एंडर बार्रेनचेया के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन एंड्रिक के शानदार चिप शॉट से रियल मैड्रिड ने बराबरी कर ली। डेविड अलाबा के आत्मघाती गोल और मिकेल ओयारज़ाबल के डिफ्लेक्टेड शॉट से सोसिएदाद को

बढ़त मिली, लेकिन मैड्रिड ने जूड बेलिंघम और ऑरेलियन चुआमेनी के गोलों से वापसी की। ओयारज़ाबल ने स्टॉपेज टाइम में दूसरा गोल कर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक खींचा, लेकिन सोसिएदाद पेनल्टी तक मुकाबला नहीं ले जा सकी। अंततः रूडिगर के हेडर ने मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया। मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोटी ने विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को शुरुआती लाइनअप में रखा, जबकि काइलियन एम्बाप्पे को आराम दिया और उनकी जगह एंड्रिक को मौका मिला। 18 वर्षीय एंड्रिक, जिन्होंने पहले चरण में एकमात्र गोल किया था, शुरूआती मिनटों में सक्रिय दिखे और एक शानदार ओवरहेड किक से गोल करने के करीब पहुंचे। बेलिंघम ने भी गोल करने की कोशिश की, लेकिन बढ़त रियल सोसिएदाद ने ली। बार्रेनचेया ने पाब्लो मारिन के पास पर बढ़त बनाते हुए गोल किया। हालांकि, मैड्रिड ने जल्द ही बराबरी कर ली।

युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप : एलिमिनेटर में युवा मुंबा का सामना युवा योद्धास से और सोनीपत स्पार्टन्स भिड़ेगी वारियर्ज के.सी. से

हरिद्वार। उत्तराखंड के वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में जारी युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप के सुपर 6 और हेड-टू-हेड मुकाबलों का रोमांचक समापन हुआ। खेले गए निर्णायक मैचों के बाद युवा मुंबा, सोनीपत स्पार्टन्स और वारियर्ज़ के.सी. ने प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। प्लेऑफ दौर में दो एलिमिनेटर, एक सेमीफाइनल और एक ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। एलिमिनेटर मुकाबलों में युवा मुंबा का सामना युवा योद्धास से होगा, जबकि सोनीपत स्पार्टन्स और वारियर्ज़ के.सी. भी नॉकआउट मैच में आमने-सामने होंगे।

दोनों मुकाबले 2 अप्रैल को खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों विजेता 4 अप्रैल को सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगे, और फाइनल मुकाबला 5 अप्रैल को होगा, जिसमें जयपुर पिंक कब्स पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है।पहले मुकाबले में युवा मुंबा ने जूनियर स्टीलर्स को 48-26 से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया। पृथ्वीराज शिंदे ने 12 अंक अर्जित कर टीम को जीत दिलाई। दूसरे मुकाबले में सोनीपत स्पार्टन्स ने पलानी टस्कर्स को 44-33 से हराया। पंकज ठाकुर (12 अंक) और अंकित सहारवा (11 अंक) ने शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे मुकाबले में वारियर्ज़ के.सी. ने चंडीगढ़ चार्जर्स को 51-34 के बड़े अंतर से हराया। नितिन सिंह 10 रेड अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे।

आईपीएल 2025:पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपरजायंट्स को आठ विकेट से हराया

एजेंसी

लखनऊ। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को आठ विकेट से हराकर इस सत्र की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 16.2 ओवर में दो विकेट पर 177 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। लगातार दो मैचों में जीत के साथ पंजाब अंक तालिका में चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई।लखनऊ की ओर से मिले 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने तेज शुरुआत की। हालांकि तीसरे ओवर में 26 के योग पर प्रियांश आर्या के रूप में टीम को पहला झटका लगा। प्रियांश ने 8 रन बनाया। इसके बाद कप्तान श्रेयश अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह का अच्छा

साथ दिया और टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। इस बीच 69 रन बनाकर प्रभसिमरन आउट हो गए। इसके बाद नेहर वढेरा और श्रेयश ने टीम को 22 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। श्रेयश 52 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि नेहल वढेरा ने 43 रन की नाबाद पारी खेली। लखनऊ के लिए दिग्वेश राठी एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, जिन्हें दो सफलता मिली। इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने खराब शुरुआत की। पारी के पहले ओवर में ओपनर मिचेल मार्श शून्य पर आउट हो गए। फिर चौथे ओवर में एडन मारक्रम (28 रन) और पांचवे ओवर में कप्तान ऋषभ पंत (02 रन) भी पवेलियन लौट गए। तब निकोलसस पूरन ने आयुष बडोनी के साथ 54 रन की साझेदारी कर टीम को पटरी पर लाने की कोशिश की। हालांकि पूरन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए और 44 रन के निजी योग पर आउट हो गए। बडोनी ने डेविड मिलर (19 रन) और अब्दुल समद (27 रन) के साथ छोटी छोटी साझेदारी कर टीम के स्कोर पर 171 तक पहुंचाया। बडोनी ने 41 रन की शानदार पारी खेली। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए। जबकि लोकी फर्गूसन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को यानसेन और यजुवेंद्र चहल को एक-एक सफलता मिली।

इटली में छाई गुजरात की मनोदिव्यांग आशाबेन, पिंकलबेन

गांधीनगर। इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स (विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल) में गुजरात की दो मनोदिव्यांग आशाबेन ठाकोर और पिंकलबेन चौहान खिलाड़ियों ने डंका बजाया है। सरकारी सूत्रों ने यहां बताया कि मेहसाणा की आशाबेन ठाकोर और दाहोद की पिंकलबेन चौहान ने ट्यूरिन में फ्लोरबॉल खेल में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम योगदान दिया। भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका वाली गुजरात की इन बेटियों ने अपने अद्भुत खेल कौशल से गुजरात और भारत का नाम रोशन किया है। फ्लोरबॉल हॉकी जैसा एक इनडोर खेल है, जिसे हल्की प्लास्टिक बॉल और विशिष्ट कार्बन फाइबर स्टिक के साथ खेला जाता है। उल्लेखनीय है कि इटली के ट्यूरिन में आठ से 15 मार्च के दौरान स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था।

एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपनः पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

एजेंसी

बेंगलुरु। बेंगलुरु के एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन के पहले दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ रावत, निकिता इयानिन, चिराग दुहान, मैक्सिम झुकोव, निक चैपल और रयूकी मात्सुदा ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

सिद्धार्थ रावत ने एक रोमांचक मुकाबले में दिग्विजय प्रताप सिंह को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। मैच के बाद रावत ने कहा, दिग्विजय लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे, जिससे मुझे कुछ अहम मौकों पर फायदा मिला। मौसम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं अपनी लय बनाए रखने में सफल रहा। निकिता इयानिन ने हितेश चौहान को तीन घंटे चले कड़े मुकाबले में 7-5, 5-7, 7-6(7) से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। जापान के रयूकी मात्सुदा ने तीसरी

वरीयता प्राप्त मोएरानी बौजिगे को 6-4, 6-4 से पराजित किया। चिराग दुहान ने चेक गणराज्य के डोमिनिक पलान को 7-6(7), 6-4 से मात दी, जबकि अमेरिका के निक चैपल ने आरपी सेंथिल कुमार को 6-3, 6-2 से हराकर आसानी से जीत दर्ज की। मैक्सिम झुकोव ने सातवीं वरीयता प्राप्त देव जाविया को 6-4, 6-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे सेट में लगातार चार गेम जीतकर मैच अपने नाम किया।

युगल मुकाबलों में भी भारतीय खिलाड़ी चमके

युगल स्पर्धा में दूसरे वरीय विष्णु वर्धन और साई गणता कार्तिक रेड्डी की जोड़ी ने ऋषि रेड्डी और इसहाक इकबाल को 6-3, 6-2 से हराया। वहीं, सिद्धांत प्रज्वल देव और नितिन कुमार सिन्हा ने कबीर हंस और अथर्व शर्मा को 6-3, 4-6, [10-3] से हराकर जीत दर्ज की। इसके अलावा, चौथी वरीयता प्राप्त आर्यन शाह और करण सिंह ने मान केशरवानी और फैसल कमर को 7-5, 6-1 से पराजित किया। शीर्ष वरीय आदिल कल्याणपुर और कोडी पियर्सन की जोड़ी ने रयूकी मात्सुदा और मोएरानी बौजिगे को 2-6, 6-3, [10-5] से हराकर शानदार वापसी की।

सीए ने 2025-26 के लिए केंद्रीय अनुबंधों का किया ऐलान, सैम कॉन्स्टस को पहली बार मिला मौका

एजेंसी

मेलबर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने 2025-26 सीजन के लिए केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची जारी की। इस बार 23 खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध मिला,जिसमें युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। यह फैसला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल और एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। महज 19 साल की उम्र में सैम कॉन्स्टस ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। उन्होंने मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 65 गेंदों में 60 रन बनाए। उनकी पारी में छह चौके और दो छक्के शामिल थे।

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बैली ने कहा, सैम में हमें एक होनहार खिलाड़ी दिखता है, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सुधार करेगा। बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन को भी इस साल अनुबंधित सूची में जगह दी गई है। 28 वर्षीय कुहनेमैन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 16 विकेट लेकर 'सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता। हालांकि, संदिग्ध गेंदबाजी

एक्शन को लेकर उन पर सवाल उठे थे, लेकिन ब्रिस्बेन के नेशनल क्रिकेट सेंटर में परीक्षण के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बैली ने मैथ्यू ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और हमें लगता है कि वह अगले 18 महीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरफनमौला खिलाड़ी ब्यू वेबस्टर, जिन्होंने इस साल भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में डेब्यू किया था, को भी अनुबंध सूची में बरकरार रखा गया है। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। बैली ने ब्यू ने टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन खेल दिखाया और बल्ले-बॉल दोनों से टीम को संतुलन दिया। उनका योगदान मैदान पर भी अहम रहा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 2025-26 सीजन के लिए केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी

जेवियर बार्टलेट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, लांस मॉरिस, झाय रिचर्डसन, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर, एडम ज़म्पा।

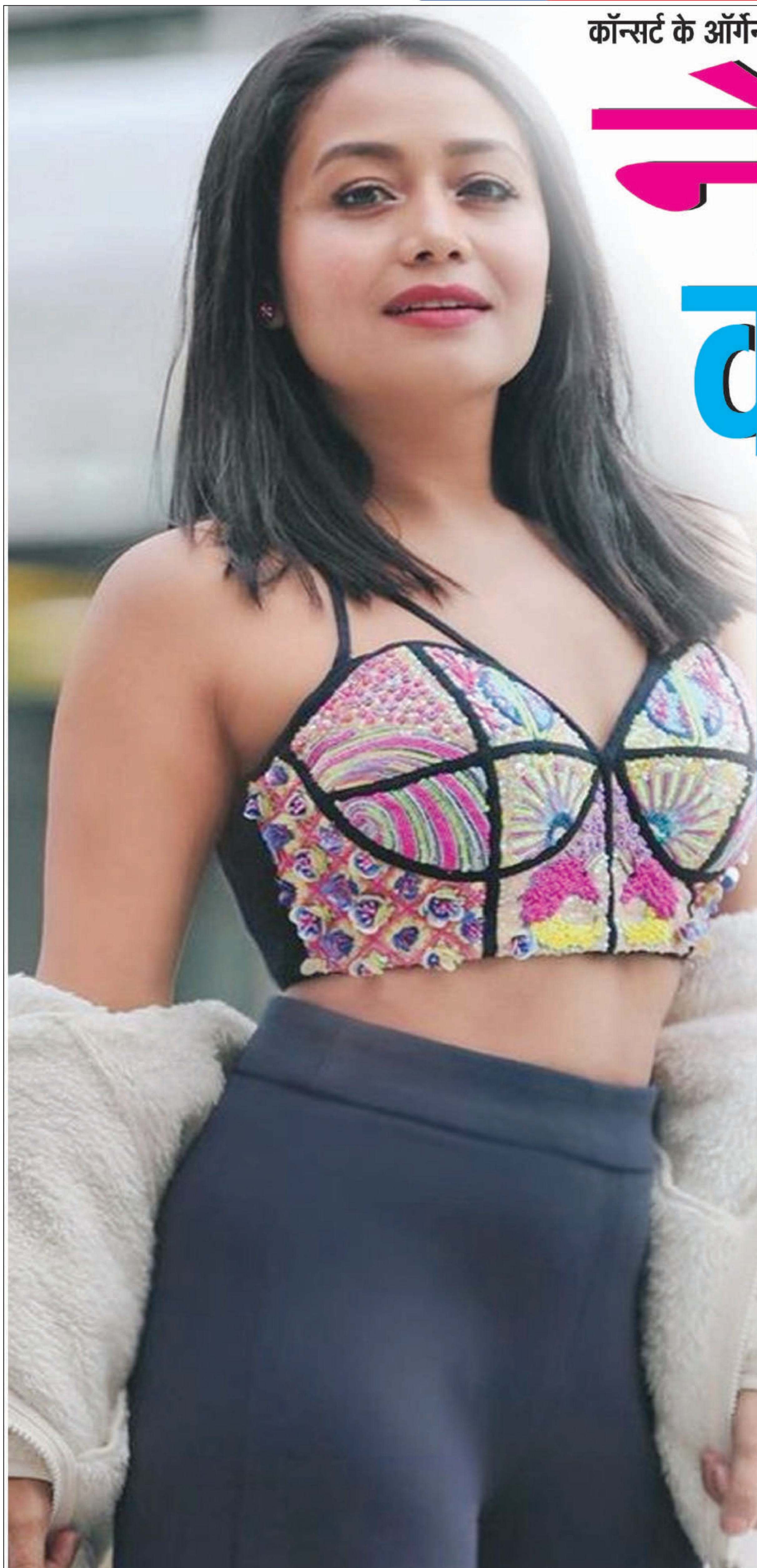

कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स का सामने आया रिएक्शन, कहा

नेहा कक्कड़

की वजह से 4 करोड़ का हुआ कर्ज

हाल में सिंगर नेहा कक्कड़ काफी चर्चा में थीं, इसकी वजह मेलबर्न में ऑर्गेनाइज हुआ उनका एक शो था. दरअसल, इस हफ्ते की शुरुआत में नेहा को मेलबर्न में परफॉर्म करना था, लेकिन वो अपने कॉन्सर्ट की टाइमिंग से करीब 3 घंटे लेट वेन्यू पर पहुंचीं. सिंगर की इस हरकत की वजह से उनका शो देखने आए हुए लोगों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद नेहा स्टेज पर ही रोने लगीं. हालांकि, इसके बाद से नेहा ने अपने सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइजर्स पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन अब इस मामले में ऑर्गेनाइजर्स का रिएक्शन सामने आ गया है.मेलबर्न में लेट होने की बाद नेहा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ऑर्गेनाइजर्स की मिसमैनेजमेंट की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ. इतना ही नहीं सिंगर ने ये भी कहा कहा कि वो उनके पैसे भी लेकर भाग गए और होटल और खाने पीने तक का भी खर्च उन्होंने नहीं दिया. हाल ही में इस मामले पर रिएक्ट करते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने इन सारे आरोपों को गलत ठहराते हुए सिंगर की वजह से हुए अपने घाटे के बारे में भी बात की है.

कॉन्सर्ट को कहा डिजास्टर

ऑर्गेनाइर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम नेहा कक्कड़ के शो के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके सभी सबूत और डिटेल के साथ वापस आएंगे. हम कल सभी को इस मामले में बेनकाब करेंगे, यह लाइव होगा. इसके बाद से शो के रिप्रेजेंटेटिव ने नेहा कक्कड़ के कॉन्सर्ट को डिजास्टर कहते हुए बताया कि शो के सारे अरेंजमेंट बिल्कुल सही थे. इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि सिंगर की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं.

4 करोड़ से ज्यादा का कर्ज

आगे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि कॉन्सर्ट की वजह से वो सभी कर्ज में डूब गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेहा कक्कड़ को ही हमें पैसे देने चाहिए, उनके साथ काम करना ही हमारे लिए गलती थी. बाद में उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से नेहा के कॉन्सर्ट में हुए सभी खर्च की डीटेल थी. इसके साथ उनकी तरफ से कैप्शन में लिखा गया कि ये सारे खर्च हैं और हम 4,53,46,111 रुपए कर्ज में हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस अनप्रोशेनल तरीके और लेट पहुंचने की वजह से उन्हें वेन्यू से बैन भी कर दिया गया है.

शाहरुख खान

की बीवी गौरी ने खेला ऐसा दांव, चुटकियों में हुई करोड़ों की कमाई

अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर शाहरुख खान एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. अपनी पत्नी गौरी खान के साथ उन्होंने 'रेड चिलीज प्रोडक्शन' की शुरुआत की थी. इसके अलावा शाहरुख एक वीएफएक्स स्टूडियो के मालिक भी हैं और उनकी पत्नी गौरी खान एक कामयाब इंटिरियर डिजाइनर हैं. शाहरुख और गौरी ने बिजनेस के साथ-साथ कई प्रॉपर्टीज में भी निवेश किया है. हाल ही में शाहरुख खान की पत्नी गौरी ने अपना एक आलीशान फ्लैट बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है.

तीन साल पहले यानी साल 2022 में गौरी खान ने मुंबई के दादर की कोहिनूर बिल्डिंग में एक 3 BHK फ्लैट खरीदा था. उस समय इस फ्लैट की कीमत 8.5 करोड़ थी. स्क्वायर यार्ड के मुताबिक अब गौरी ने अपना ये फ्लैट 11.61 करोड़ में बेच दिया है. गौरी को फ्लैट बेचने पर तगड़ा मुनाफा हुआ है.

गौरी को इतना हुआ प्रॉफिट

आंकड़ों की बात करें को, इस पूरी रियल इस्टेट डील में गौरी को लगभग 37त्न (3 करोड़) का मुनाफा हुआ है. द्बलत्र संपत्ति दस्तावेजों के मुताबिक गौरी द्वारा बेचे गए इस अपार्टमेंट का एरिया 1,985.04 स्क्वायर फीट है. इसका कारपेट एरिया 1,803.94 स्क्वायर फीट है, इसके अलावा इस फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग की भी सुविधा भी दी गई है. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में 27.16 लाख रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट साथ 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी शामिल किया गया है.

रेस्त्रां बिजनेस में भी कर चुकी हैं एंट्री

नेटफ्लिक्स की मशहूर रियलिटी टीवी सीरीज 'द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में अपनी झलक दिखा चुकीं गौरी खान ने अब रेस्त्रां बिजनेस में भी एंट्री कर ली है. मुंबई में उन्होंने 'टोरी'

नाम का पैन एशियाई रेस्त्रां शुरू किया है. इस बिजनेस के अलावा वो फिल्में भी प्रोड्यूस कर रही हैं और साथ ही खुद का इंटीरियर का बिजनेस भी चला रही हैं. अनन्या पांडे, करण जौहर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने करोड़ों के अपार्टमेंट को सजाने की जिम्मेदारी गौरी खान.

'महाकुंभ' की मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार, रेप केस में हुए अरेस्ट

महाकुंभ मेले में वायरल हुई माला बेचने वाली मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस ने रेप के एक मामले में डायरेक्टर को अरेस्ट किया है. दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. डायरेक्टर सनोज पर आरोप है कि उन्होंने झांसी की रहने वाली एक युवती को फिल्म में काम दिलाने का लालच दिया. इसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया गया. वहीं धमकियां देकर उसे चुप रखने का भी आरोप है.पीड़िता के मुताबिक, 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी सनोज मिश्रा से मुलाकात हुई थी. उस वक्त वो पीड़िता झांसी में रहती थी. काफी वक्त तक दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर डायरेक्टर ने 17 जून 2021 को उसे फोन किया. साथ ही जानकारी दी गई कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पर है.

डायरेक्टर सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी

पीड़िता का कहना है कि, जब उसने समाज के दबाव का हवाला देते हुए मिलने से मना किया, तो आरोपी ने उसे आत्महत्या करने की धमकी दी. इस डर के चलते वो उससे मिलने चली गई. अगले ही दिन यानी 18 जून 2021 को आरोपी ने फिर फोन किया. एक बार फिरआत्महत्या की धमकी देते हुए उसे रेलवे स्टेशन बुलाया गया था.

डायरेक्टर पर क्या आरोप है ?

मोनालिसा को जिस डायरेक्टर ने फिल्म का ऑफर दिया था. उस पर आरोप है कि डायरेक्टर पीड़िता को एक रिसॉर्ट में लेकर गया. साथ ही उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया. वहीं पीड़िता ने FIR में बताया है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बनाए हैं. साथ ही उसे लेकर धमकी भी दी. उसे कहा गया कि अगर उसने विरोध किया, तो वो इन्हें वायरल कर देगा.

शादी का दिया गया झांसा: पीड़िता

पीड़िता ने कहा कि, इसके बाद उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग-अलग जगहों पर बुलाया गया. साथ ही शारीरिक संबंध बनाए गए थे. उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया गया था. इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई आ गई और आरोपी के साथ रहने लगीं.

सलमान-आमिर खान मिलकर इमरान के लिए बनेंगे 'खतरा'? इस दिन आ रही दोनों की ये बड़ी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च को रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छा खासा कलेक्शन किया है. इस फिल्म की चर्चाओं के बीच अब सलमान खान के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आई है. इतना ही नहीं इस खबर से आमिर खान के फैंस भी खुश हो जाएंगे. दोनों स्टार्स की 30 साल पुरानी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' री रिलीज होने जा रही है.सलमान खान और आमिर खान की इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाया था. कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को हर किसी ने प्यार दिया था. अंदाज अपना अपना 30 साल पहले रिलीज हुई थी. जबकि अब ये दोबारा दस्तक देने के लिए तैयार है. जानते हैं कि फिल्म कब री-रिलीज हो रही है ?

कब री-रिलीज होगी 'अंदाज अपना अपना' ?

अंदाज अपना अपना में सलमान और आमिर के साथ रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जैसी मशहूर अदाकाराओं ने लीड रोल प्ले किया था. इसका डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था और प्रोड्यूसर थे विनय कुमार सिन्हा. दिवंगत विनय सिन्हा की फैमिली ने नवंबर 2024 में फिल्म के 30 साल पूरे होने के मौके पर बताया था कि फिल्म 2025 में गर्मियों के दिनों में फिर से दस्तक दे रही है. फाइनली अब इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया गाया है.टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए विनय सिन्हा

की फैमिली ने इसकी री रिलीज डेट का खुलासा किया है. विनय के बच्चों नम्रता, प्रीति सिन्हा और आमोद सिन्हा ने बताया कि 25 अप्रैल 2025 को 'अंदाज अपना अपना' दोबारा रिलीज होने जा रही है. साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि आमिर और सलमान इसके सीक्वल के लिए भी एक्साइटेड हैं.

इमरान की 'ग्राउंड जीरो' से होगा क्लैश

आमिर खान और सलमान खान की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' इमरान हाशमी की फिल्म 'ग्राउंड' जीरो के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है. फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है. इमरान की ग्राउंड जीरो भी 25 अप्रैल को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म में इमरान एक बीएसएफ कमांडर के दमदार किरदार में दिखाई देंगे. हाल ही में इसका टीजर जारी हुआ है जिसने फैंस का ध्यान खींचा है.

ट्रंप के टैरिफ बम से भारत के कई सेक्टर का निकला दिवाला

नई दिल्ली अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी से दुनिया के ज्यादातर देश प्रभावित होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करने के बाद से ही लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि भारत के किस सेक्टर पर इसका कितना असर पड़ेगा। इस नई टैरिफ पॉलिसी के कारण भारत में कई सेक्टर्स पर निगेटिव असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, तो कई सेक्टर्स को फायदा होने की भी संभावना है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का ऐलान होने के बावजूद भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सबसे अधिक राहत मिली है, क्योंकि अमेरिका ने इस सेक्टर को टैरिफ से बाहर रखा है। इसकी वजह से अमेरिका में अपनी दवाओं का निर्यात करने वाली डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज, अरबिंदो फार्मा और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों को काफी राहत मिली है। इन कंपनियों के कुल राजस्व में 33 से लेकर 50 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी अमेरिका को किए गए निर्यात की होती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी में स्टील, कॉपर, सोना-चांदी समेत कुछ खास खनिजों को भी रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसा होने से इन सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियों पर भी अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी में अपैरल इंडस्ट्री पर भी टैरिफ का बोझ डाला गया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ के बोझ के बावजूद भारत को इस सेक्टर में फायदा मिल सकता है। अमेरिका के अपैरल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 6 प्रतिशत की है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत और वियतनाम की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में चीन पर कुल 54 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, वहीं वियतनाम पर 46 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जबकि भारत पर टैरिफ का बोझ 26 प्रतिशत का है। ऐसे में भारत के अपैरल प्रोडक्ट्स की तुलना में चीन के उत्पादों पर 28 प्रतिशत और वियतनाम के उत्पादों पर 20 प्रतिशत अधिक टैरिफ का बोझ रहेगा। स्वाभाविक है कि टैरिफ के इस बड़े अंतर के कारण इंडियन अपैरल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में नई व्यवस्था में भी चीन और वियतनाम के उत्पादों की तुलना में सस्ते पड़ेंगे।

चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई: राहुल

'हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे'

नई दिल्ली
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा- हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने कहा- एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया। इससे देश की ऑटो, फार्मास्यूटिक्ल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राहुल ने कहा- एक बार किसी ने इंदिरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया की मैं बाएं या दाएं नहीं झुकती। मैं भारतीय हूं और सीधी खड़ी हूं।
भाजपा और फ्रर की फिलॉस्फी अलग है। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं नहीं, नहीं, हम हर विदेशी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह उनके इतिहास में है, हम जानते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह अमेरिकी टैरिफ पर क्या कर रही है। बीते दिन अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत जैसे को तैसा टैक्स लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) लगाता है। राहुल गांधी ने 2022 में लद्दाख दौरे पर कारगिल में रैली की थी। वहां उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की हजारों किमी जमीन पर कब्जा किया है।

गरीबी के खिलाफ और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त करने के लिए जंग छेड़ने की जरूरत: मनोज झा

नई दिल्ली
राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए राजद के प्रो. मनोज कुमार झा ने कहा कि आज हमें ज्यादा जरूरत गरीबी के खिलाफ और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त करने के लिए जंग छेड़ने की है। प्रो. झा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के एक पुराने बयान को कल से सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि, इससे अधिक संख्या में उनके सांप्रदायिक एकता के बयान हैं लेकिन उन बयानों को तवज्जो नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुमत मिलना बुद्धिमत्ता की गारंटी नहीं होता है। आए दिन कभी-कभार पूजा स्थलों पर सवाल उठता है। खान, पान, पूजा, इबादत पर इतनी तकरार क्यों है हम समुदायों को लगातार हाशिए पर छोड़ रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का जिक्र करते हुए कहा कि उसके पात्र हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा था लेकिन उन्होंने नहीं लिखा कि वह किस जाति या मजहब वाले की दुकान से खरीदा। आज इस देश में दुकानदारों को मजहबी आधार पर चिह्नित किया जाता है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2343 टावर लगाने की योजना: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली
राज्यसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियानेकहा कि सरकार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2343 मोबाइल टावर लगाए जाने की योजना बनाई है। गुरुवार को एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4जी में अपग्रेडेशन और बीएसएनएल टावरों के बंद होने पर उठाए जाने वाले उपायों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि डिजिटल भारत निधि के तहत एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2343 टावरों की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में वे पूंजीगत व्यय के लिए एक योजना बना रहे हैं, जिसके तहत बीएसएनएल के 2.5 लाख टावरों के लिए, जहां भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी, प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्त मंत्री से फंड की मांग करेंगे या इसके लिए बीएसएनएल की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर

26 प्रतिशत का शुल्क लगाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को एलन मस्क के स्टारलिंक के लिए आवश्यक अनुमतियों को रोककर ट्रम्प टैरिफ पर फिर से बातचीत करने के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी भारत में दूरसंचार के 1.4 बिलियन उपभोक्ताओं के प्रति है। उन्हें सभी उपलब्ध अवसर और तकनीक प्रदान करना उनका काम है। उन्होंने कहा कि भारत में सैटेलाइट तकनीक के लिए अब तक केवल दो लाइसेंस भारतीय कंपनियों- रिलायंस और भारती एयरटेल को दिए गए हैं। हमारे पास एक स्पष्ट व्यवस्था है, जो उपभोक्ताओं और भारत की सुरक्षा चिंताओं का ख्याल रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता दूरसंचार बाजार भी है।
इस उत्तर को आगे बढ़ाते हुए संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि भारत के स्थलीय नेटवर्क की ब्रॉडबैंड स्पीड स्टारलिंक या किसी अन्य सैटेलाइट नेटवर्क की तुलना में 188 गुना अधिक है और पिछले 3 वर्षों में स्टारलिंक का वैश्विक उपयोगकर्ता आधार भारत के नेटवर्क की पहुंच की तुलना में केवल 46 लाख है।

ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने का जिम्मा सौंपा है, जिससे सदन में सदस्य मर्यादित आचरण करें: धनखड़

नई दिल्ली
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता वाली संसदीय आचार समिति (एथिक्स कमेटी) को ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने का जिम्मा सौंपा है, जिससे सदन में सदस्य मर्यादित आचरण करें और संसदीय संस्थान की साख में इजाफा हो। लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बारे में दिए गए बयान को लेकर आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ यह सब देखकर भावुक हो गए। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस

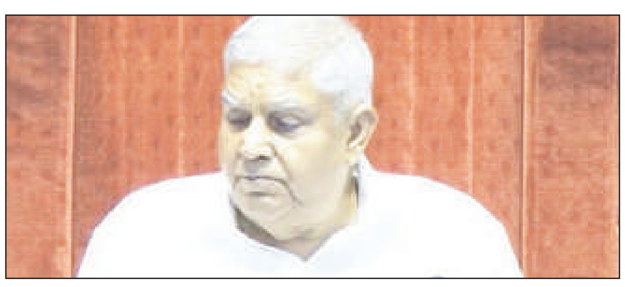

सदन में और दूसरे सदन में बहुत वरिष्ठ लोगों के संबंध में सभी प्रकार की बातें की गई हैं। खरगे सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक हैं। मैं प्रधानमंत्री सहित संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य वरिष्ठ लोगों के संबंध में जो कहा गया है, वह यहां नहीं कहना चाहता। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि चाहे प्रधानमंत्री हों, सदन के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, मेरे लिए हर सदस्य की अपनी एक अनमोल प्रतिष्ठा है, जिसे बनाए रखना है और इसलिए जो कुछ भी हटाया गया (एक्सपंज) है, उसे कभी भी चर्चा में नहीं आना चाहिए।

ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन करेगा भारत: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत पारस्परिक टैरिफ वृद्धि और देश पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आईआईएम, अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित 'प्रथम

पेंशन शोध सम्मेलन' में कहा कि भारत पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव की समीक्षा और आकलन करेगा। पंकज चौधरी ने कहा कि "ट्रंप के लिए यह अमेरिका पहले है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह भारत पहले है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।" वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका की शुल्क बढ़ोतरी और देश पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

ईपीएफओ ने दो प्रमुख सुधारों के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाया

नई दिल्ली
सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपनी प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से दावा निपटान प्रक्रिया में दो अहम बदलाव किए हैं। ईपीएफओ के इस कदम से करीब 8 करोड़ अंशधारकों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ईपीएफओ के अनुसार अब भविष्य निधि से ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चेक की तस्वीर ह्यअपलोडह्ण करने की आवश्यकता नहीं है और उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को हटाने से ईपीएफओ के 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाने से लंबित अनुमोदन वाले करीब 15 लाख सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के इन उपायों से दावा निपटान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और दावा खारिज होने से संबंधित शिकायतों में भी आएगी।

चेक लीफ/सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता हटाना

ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावे दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को समाप्त कर दिया है। 28 मई, 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद से इस कदम से 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है।
सफल पायलट आधार के बाद ईपीएफओ ने अब यह छूट सभी सदस्यों के लिए बढ़ा दी है।

भारत-थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली
भारत और थाईलैंड ने गुरुवार को बैंकॉक के गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और थाई प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के बीच वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्री विरासत, लघु व्यवसाय और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का

आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में कहा, ह्यभारत-थाईलैंड हमारी दीर्घकालिक मित्रता में नई ऊर्जा और गतिशीलता जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बैंकॉक में गवर्नमेंट हाउस में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के साथ एक सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की और भारत-थाईलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रवक्ता ने समझौतों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों व एमओयू पर हस्ताक्षर एवं आदान-प्रदान हुआ।

अब सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा

नई दिल्ली
न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा। एक अप्रैल को हुई फुल कोर्ट बैठक में सभी जजों ने यह फैसला लिया है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जजों को पदभार ग्रहण करने पर या जब भी उनकी संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण चीज जुड़ती है, तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को देंगे।
खुद चीफ जस्टिस भी ऐसा करेंगे। इसके बाद इन संपत्ति के ब्यौरे की जानकारी सम्बंधित जज की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे ने दिल्ली में किया 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर लॉन्च

दिव्या दिल्ली: आखिरकार, बहुप्रतीक्षित फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर आउट हो ही गया। 'केसरी चैप्टर 2' का यह ट्रेलर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द इंपीरियल होटल में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और आर माधवन ने अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अभिनेताओं से सजा फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया। यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। 'केसरी चैप्टर 2' फिल्म वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सी शंकरन नायर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में 'केसरी चैप्टर 2' के निमार्ताओं करण जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल

बिंद्रा के साथ फिल्म के निर्देशक करण सिंह त्यागी भी मौजूद थे। फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए अक्षय कुमार ने भी लिखा, '1650 गोलियां, 10 मिनट और एक आदमी, जो इसके खिलाफ दहाड़ता है। भारत को हिला देने वाले भयानक नरसंहार के पीछे की सच्चाई को देखें।'

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397